राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उत्तरांचल,उत्तराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात,संस्करण गुरुवार,१० दिसंबर २०२० वर्ष-३, अंक -३११ पृष्ठ-०८ मूल्य-०१रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अब सिर्फ कोरोना वैक्सीन की मंजूरी का है इंतजार, टीकाकरण को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार

नई दिल्ली। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की तैयारियां करीब-करीब पूरी कर ली गई हैं। बस, टीके को नियामक की मंजूरी मिलने का इंतजार है। सरकार ने कहा कि टीके को मंजूरी मिलने के कुछ समय बाद टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण एवं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने मंगलवार को कहा कि औषधि नियामक कोरोनारोधी के तीन टीकों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इनमें से सभी को या किसी एक-दो को जल्द लाइसेंस दिए जाने की संभावना है। एक करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों एवं दो करोड़ अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को सबसे पहले टीका लगाने की तैयारी है। टीकाकरण की तैयारियां की जा चुकी हैं। को-विन सॉफ्टवेयर पर अग्रिम मोर्चे के स्वास्थ्यकर्मियों के बारे में आंकड़ा अपलोड किया जा रहा है। इसके जरिए पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी जाएगी।

हर जरूरतमंद को लगेगा टीका

पहली श्रेणी- एक करोड़ लोग- केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण को लेकर बनाए गए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) ने सबसे पहले कोरोना टीका स्वास्थ्यकर्मियों को देने की सिफारिश की है। इनमें केंद्र, राज्य एवं निजी क्षेत्र के कार्मिकों को मिलाकर करीब एक करोड़ लोग आते हैं।

दूसरी- दो करोड़- दूसरी प्राथमिकता अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को देने की बात कही है। इसमें पुलिस, सुरक्षाबल, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, निगम कार्मिक आदि आते हैं। इस श्रेणी में करीब दो करोड़ लोग आते हैं।

तीसरी- 27 करोड़- तीसरे प्राथमिकता समूह में 50 साल से अधिक और कम उम्र के उन लोगों को टीका देने की सिफारिश की गई है, जो किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं। ऐसे लोगों की सख्या 27 करोड़ है।

किसानों ने सरकार का प्रस्ताव किया खारिज, बोले-जारी रहेगा प्रदर्शन

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा था लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान नेताओं का साफ कहना है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। 12 दिसंबर को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कराएंगे। 14 दिसंबर को देश भर में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा है कि सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करे। दूसरी तरफ किसानों द्वारा प्रस्ताव खारिज किए जाने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं।

क्या था सरकार के प्रस्ताव में?

बता दें कि आज (बुधवार) सरकार की ओर से आंदोलन कर रहे किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क्र) का जिक्र किया गया था। इसके अलावा सरकार की ओर से प्रस्ताव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत देने और प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने की बात की गई थी। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को छठे दौर की बातचीत के लिए निमंत्रण भी दिया था।

मुख्य बातें-

- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में संशोधन कर कोर्ट जाने के अधिकार को शामिल करने को सरकार राजी है।

- प्राइवेट प्लेयर अभी पैन कार्ड की मदद से काम कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने पंजीकरण व्यवस्था की बात कही। सरकार इस शर्त को मानने को तैयार है।

- इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स पर कुछ टैक्स की बात भी सरकार मानने को तैयार है।

-एमएसपी खत्म नहीं होगा।

कृषि मंत्री कर चुके हैं स्थिति स्पष्ट

किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरने एक बार फिर नए कृषि कानूनों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानूनों का सच हर किसी को जरूर जानना चाहिए ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे। कृषि मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 'कृषि कानून एमएसपी सिस्टम और एपीएमसी मंडियों को प्रभावित नहीं करते हैं। किसान फसल उगाने से पहले ही उपज के दाम तय कर सकते हैं। खरीदारों को समय पर भुगतान करना होगा वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।'

कृषि मंत्री ने कहा है कि इन कानूनों के चलते किसान की जमीन किसी भी कारण से कोई नहीं छीन सकता है। खरीदार किसान की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठेकेदार पूर्ण भुगतान के बिना अनुबंध समाप्त नहीं कर सकता है।

ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज करने के लिए 2 दिन बंगाल में रहेंगे जेपी नड्डा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष जोपी नड्डा बुधवार को पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे, जिसमें पार्टी के कैडर को मजबूत करने के साथ-साथ बूथ स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे।

जेपी नड्डा बंगाल में राज्य के नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे। इस दौरान वे भाजपा के नौ कार्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि नड्डा भवानीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के मिशन और नोई अन्याय (और नहीं अन्याय) को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव की तैयारी के लिए 117 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन टीम का गठन किया है। टीमों को 31 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इन टीमों के पास पार्टी के लिए अभियान, डेटा संग्रह, बूथ प्रबंधन और सोशल मीडिया प्रबंधन तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों को राज्य में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो पार्टी की चुनावी योजना का रणनीतिकार हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल में थे। नड्डा का दौरा उनके 120 दिनों के राष्ट्रीय दौरे का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश भर में पार्टियों की उपस्थिति को मजबूत करना है। 10 दिसंबर को, भाजपा अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और 24 परगना पूर्व से पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और मछुआरा समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के जज कोरोना वायरस से हुए रिकवर

लोगों से की कोविड-19 गाइडलाइन्स फॉलो करने की अपील

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर बना हुआ है। घर में पड़े-पड़े लोगों तक भी संक्रमण पहुंच रहा है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस कृष्ण मुरारी भी कोरोना वारस से संक्रमित हुए। लेकिन रिकवर होकर जब वो अदालत में आए तो लेकिन पूरा दिन वहां बने नहीं रह सके। तीन जजों की बेंच बाद में दो जजो की ही रह गई। जस्टिस कृष्ण मुरारी को आराम करने के लिए कह दिया गया। रोहिंटन एफ नरीमन के साथी जज जस्टिस कृष्ण मुरारी के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की जिसके बाद सभी को पता चला गया कि कृष्ण मुरारी कोरोना वायरस से ग्रसित थे और ठीक होने के बाद ये उनका पहला दिन था. न्यायमूर्ति नरीमन ने अदालत में घोषणा की। जस्टिस मुरारी एक कोरोना वायरस के भयानक हमले से उबर चुके हैं। मैंने उन्हें सलाह दी कि वह आज भी न आए लेकिन वह फिर भी कुछ समय के लिए बैठना चाहता थे। उन्होंने तब न्यायमूर्ति मुरारी को संबोधित किया भाई, यह मामला लंबे समय तक चलेगा। हम इसे दो जजों की बेंच के मामले के रूप में सुन सकते हैं। आप कृपया आराम करें। और अपना ख्याल रखना। न्यायमूर्ति मुरारी, जिन्होंने एक घंटे से अधिक की कार्यवाही के बाद थका हुआ देखा, ने सलाह को स्वीकार कर लिया। यह पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को कोरोना वायरस हुआ। न्यायाधीश से बात की, जिन्होंने कहा कि लोगों को अपनी सावधानियों को कम नहीं होने देना चाहिए क्योंकि महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ÷मैं बहुत से लोगों के साथ बातचीत या मुलाकात नहीं करता हूं। मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे ये कैसे हुआ। इसलिए, मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि सावधानियों की अवहेलना कभी न करें। सभी को मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइटर का उपयोग करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना चाहिए। न्यायमूर्ति मुरारी ने अदालत में बैठकर अचानक कमजोरी महसूस करने के एक दिन बाद 19 नवंबर को सकारात्मक परीक्षण किया।

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बैग का वजन कम करने का दिया सुझाव

नई मशीनें रखने और परिसर में पेय जल उपलब्ध कराने जैसी सिफारिश की हैं। साथ में पहियों वाले बैगों पर रोक लगाने की भी अनुशंसा की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप की गई सिफारिशों में कक्षा एक से 10वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में किए गए शोध अध्ययन के आधार पर स्कूल बैग मानक भार को लेकर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की सिफारिश है और यह सार्वभौमिक तौर पर स्वीकार की जाती है। स्कूलों से कहा है गया है कि वे वजन करने वाली डिजिटल मशीनें विद्यालय परिसर में रखें और नियमित आधार पर स्कूल के बैग के वजन की निगरानी करें।

शिक्षा मंत्रालय ने दूसरी कक्षा तक गृह कार्य नहीं देने व स्कूल बैग का वजन कम करने का सुझाव दिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप की गई सिफारिशों में कक्षा एक से 10वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

नीति दस्तावेज में कहा गया है कि पहिये वाले बैग पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते वक्त यह बच्चे को चोटिल कर सकते हैं। उसमें कहा गया है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जो सुविधाएं उन्हें अनिवार्य रूप से प्रदान करनी चाहिए, विद्यालय उन्हें पर्याप्त मात्रा और अच्छी गुणवत्ता में उपलब्ध कराएं जैसे मध्याह्न भोजन ताकि बच्चे घर से टिफिन जैसे सामान लेकर नहीं आएं। नीति दस्तावेज में कहा गया है कि स्कूल या कक्षा के समय को लचीला बनाने की जरूरत है और बच्चों को खेल एवं शारीरिक शिक्षा तथा स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के अलावा किताबें पढ़ने का पर्याप्त समय दिया जाए। नीति में कहा गया है कि दूसरी कक्षा तक कोई गृह कार्य नहीं दिया जाए और नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रोजाना अधिकतम दो घंटे का गृह कार्य दिया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि तीसरी, चौथी और पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को हफ्तें में अधिकतम दो घंटे का गृह कार्य दिया जा सकता है। छठीं से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को अधिकतम एक घंटे का गृह कार्य दिया जाना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर-पुलवामा में सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के तिकेन इलाके में सुरक्षा कर्मियों की आंतकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें दो आतंकी मारे गए। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, मठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए, ऑपरेशन अभी जारी है। आगे की जानकारी दे दी जाएगी। बता दें कि पुलवामा के तिकेन इलाके में बुधवार तड़के मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस और सुरक्षा बल अब भी ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों का ऑपरेशन अभी जारी है, आगे की जानकारी के लिए अभी इंतजार करेना होगा।

ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी फाइजर की कोविड वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी, दिखे संकेत

नई दिल्ली। अमेरिका ने फाइजर की कोविड -19 वैक्सीन का अपना पहला वैज्ञानिक मूल्यांकन जारी किया है और इसकी पुष्टि की है कि यह मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही कहा है कि सरकार इसे हरी झंडी दे सकती है। अमेरिका के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल में कहा था कि अमेरिकियों को कोरोना वायरस वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और इसके प्रभाव और सुरक्षा के बारे में चिंतित लोगों के लिए वह सार्वजनिक रूप से टीकाकरण कराने के लिए तैयार हैं। जो बाइडेन ने वैक्सीन के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह अनिवार्य होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि यह अनिवार्य हो, ठीक वैसे ही जैसे मुझे नहीं लगता मास्क अनिवार्य हो। इधर, ब्रिटेन ने मंगलवार को फाइजर और जर्मन पार्टनर बायोएनटेक के टीके के साथ पहले ही टीकाकरण शुरू कर दिया है। एफडीए इस महीने के अंत तक मोडर्ना की वैक्सीन पर विचार करेगा। गौरतलब है कि ब्रिटेन के बाद बहरीन दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने दवा निर्माता कंपनी फाइजर और उसके जर्मन सहयोगी बायोनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी दी है। बहरीन की सरकारी संवाद एजेंसी ने बीते शुक्रवार रात को इसकी घोषणा की। एजेंसी ने बताया, उपलब्ध आंकड़ों के गहन विश्लेषण और समीक्षा के बाद बहरीन के स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। हालांकि, बहरीन ने यह नहीं बताया कि उसने टीके की कितनी खुराक खरीदी है और टीकाकरण कब शुरू होगा। एसोसिएटेड प्रेस के सवाल का भी बहरीन की प्राधिकारियों ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। बाद में फाइजर ने बताया कि बहरीन को टीके की आपूर्ति और खुराकों की संख्या सहित बिक्री का समझौता गुप्त है और विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि बहरीन पहले ही चीन निर्मित टीके साइनोफार्म के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है और अबतक 6,000 लोगों के ये टीके लगाए हैं।

COVID
19
Coronavirus
Vaccine

दिल्ली में दूसरे दिन भी दिखी कोहरे की घनी चादर, हवा की गति धीमी रहने से बरकरार रहा प्रदूषण

नई दिल्ली। दो दिनों से दिल्ली के ऊपर घने कोहरे चादर बनती दिखाई दे रही है। एक दिन पहले भी दिल्ली में कोहरा देखा गया और अब भारत के मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सुबह कोहरे का असर देखा गया। आईएमडी वैज्ञानिकों के अनुसार, सफदरजंग वेधशाला (शहर के मौसम के लिए आधिकारिक मार्कर) के साथ-साथ पालम मौसम केंद्र पर सुबह के समय मध्यम कोहरा देखा गया, जिससे दृश्यता 300 मीटर से भी कम हो गई। सोमवार को शहर ने पालम में दृश्यता कम हुई थी, ये सीजन का पहला घना कोहरा था जो दिल्ली ने देखा था। दिल्ली ने मंगलवार को बेहद खराब क्षेत्र में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 दर्ज किया। हालाँकि, विवेक विहार, आनंद विहार, नरेला, जहाँगीरपुरी, नेहरू नगर, पंजाबी बाग जैसे कई निगरानी स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी (400 और अधिक का एक्यूआई मूल्य) में थी। आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, उच्च नमी की मात्रा, जो कि तेज हवाओं के परिणामस्वरूप थी, मंगलवार को कम होने लगी और इसलिए कोहरे की तीव्रता कम थी। हमें उम्मीद है कि अगले तीन से चार दिनों में कोहरा मध्यम श्रेणी में आ जाएगा, हालांकि नमी कम हो गई है, हवा की गति में अधिक वृद्धि नहीं हुई है और इसलिए हवा की गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले सप्ताह में हवा की गुणवत्ता में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। मंगलवार को हवा की औसत गति 5-6 किमी प्रति घंटा थी, जो प्रदूषकों के फैलाव के लिए अनुकूल नहीं थी। हवा की गति अगले तीन दिनों में लगभग 10 किमी प्रति घंटे रहने की संभावना है। इसके अलावा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली 11 दिसंबर को बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जो पूरे उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगी। कम से कम 12 दिसंबर तक सुबह और रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अधिकतम 28.3 डिग्री पर, सामान्य से चार डिग्री अधिक। सिस्टम फॉर एयर क्वॉलिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालय की एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग विंग, शहर के पीएम 2.5 के स्तर में जलने वाले मल का हिस्सा नगण्य था।

संपादकीय

राजनीति से अपेक्षा

किसानों के समर्थन में आयोजित कल का भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, तो यकीनन इसके लिए प्रशासन और आंदोलनकारी, दोनों की सराहना की जाएगी। इस बंद को देश की ज्यादातर विपक्षी पार्टियों और अनेक सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया था और यही वजह है कि कई राज्यों में इसका असर दिखा भी है। दरअसल, किसानों और जवानों के प्रति भारत में एक विशेष अनुराग का भाव शुरू से रहा है। इसलिए उनकी मांगों से आम जनता को कभी शिकायत नहीं होती। सरकारों का रवैया भी उनके प्रति अमूमन संजीदगी और सहानुभूति भरा ही रहता है। नए कृषि कानूनों से जुड़े मौजूदा विवाद में भी सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ताओं से साफ है कि बातचीत से एक संतोषजनक रास्ता निकालने की कवायद की जा रही है। बहरहाल, भारत बंद को जिस बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया, इसका नैतिक पहलू तो खैर अपनी जगह है ही, मगर इसके अलग राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। यह एक सच्चाई है कि भाजपा विरोधी पार्टियां केंद्र सरकार की कतिपय नीतियों के विरुद्ध अपने बूते देश भर में कोई राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने में खुद को असमर्थ पा रही थीं, ऐसे में, किसानों को हासिल व्यापक जन-सहानुभूति के सहारे उन्होंने अपनी भूमिका रची है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, खासकर इसके पश्चिमी हिस्से में किसान एक बड़े वोटबैंक भी हैं और इन राज्यों में राजनीतिक रूपरेखा तय करने में उनका अहम रोल होता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के शुरुआती महीनों में ही होने वाले हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को स्वाभाविक ही उन मुद्दों और मौकों की तलाश होगी, जो उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करे। और इसमें कोई दोराय नहीं कि किसान आंदोलन में एनडीए विरोधी पार्टियों ने वह मौका ढूंढ़ लिया है। कुछ विपक्षी पार्टियां तो पुराने रुख से कलाबाजी मारते हुए किसानों के साथ आ खड़ी हुई हैं। किसान आंदोलन की मांगों और चिंताओं के लिहाज से भारत बंद कितना फलदायी रहा, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन कृषक नेताओं ने अब तक जिस तरह से मुख्यधारा के राजनेताओं को अपने मंच से दूर रखा और परोक्षतः उनका समर्थन भी जुटाया, इससे उनकी अक्लमंदी तो झलकती ही है। भारतीय लोकतंत्र में अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के जो रास्ते संविधान ने नागरिकों, राजनीतिक दलों को दिए हैं, उनके इस्तेमाल से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती? लेकिन कोई भी परिपक्व लोकतंत्र अपने राजनीतिक दलों से यह भी अपेक्षा करेगा कि वे समाधान का पुल बनें। किसान आंदोलन के समाधान में जिम्मेदार पार्टियों को यह भूमिका भी अपनानी चाहिए। कोराना और आर्थिक बदहाली के मद्देनजर भी इस गतिरोध को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। इतनी सर्दी में खुले आकाश के नीचे बैठे हजारों किसानों और सरकार के बीच संवाद तो चल ही रहा है। पर उनके रुख को लचीला बनाने में देश के तमाम राजनीतिक दल अहम रोल निभा सकते हैं, और इसमें राजग के घटकों और विरोधी पार्टियों, सबको सहयोग करना चाहिए। दुर्योग से हम एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति के शिकार बनते जा रहे हैं, जिसमें राजनीतिक दलों के बीच अपसी संवाद की गुंजाइश लगातार सिकुड़ती जा रही है।

बंद के मायने

केंद्र सरकार के नये कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का मंगलवार को आहूत बंद कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ही कहा जा सकता है। कांग्रेस समेत दो दर्जन राजनीतिक दल भी इस विरोध के समर्थन में उतरे। वहीं कुछ ट्रेड यूनियनों ने भी बंद का समर्थन किया। महाराष्ट्र, ओडिशा व उत्तर प्रदेश में ट्रेन रोकने की कुछ घटनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को बंद किये जाने के अलावा बंद कमोबेश सामान्य ही रहा। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां बंद का प्रभाव राजनीतिक दलों की सक्रियता से कुछ ज्यादा प्रतीत हुआ। वैसे किसान संगठनों ने चिकित्सा संस्थानों, एंबुलेंस तथा आवश्यक वस्तुओं को बंद से अलग रखने का आह्वान किया था। निस्संदेह, दिल्ली बॉर्डर पर तेरहवें दिन जारी रहे किसान आंदोलन की छठे दौर की बातचीत पर बंद की छाया जरूर रहेगी। पांच दौर की वार्ता की विफलता के बाद आज केंद्र सरकार से आंदोलनकरियों की बातचीत होनी है। अब सवाल उठाया जा रहा है कि भारत बंद के बाद किसानों की रणनीति क्या होगी? क्या सरकार पर बंद से कोई दबाव बढ़ेगा? क्या सरकार का रुख बंद के बाद सख्त होगा या वह कदम पीछे खींचेगी? क्या मोदी सरकार उन किसानों को मनाने में सफल होगी, जो कह रहे हैं कि वे छह माह का राशन लेकर आंदोलन करने आये हैं। यह भी देखना होगा कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के किसानों द्वारा आहूत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरने को मोदी सरकार किस तरह लेती है। निस्संदेह, किसान आंदोलन मोदी सरकार के लिये बड़ी चुनौती बना हुआ है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी जिस तरह किसान आंदोलन का समर्थन जारी है, वह केंद्र सरकार पर एक दबाव जरूर बनायेगा। वह भी तब जब किसान आंदोलन पंजाब की अस्मिता से जोड़ा जाने लगा है और किसान आंदोलन के समर्थन में सम्मान-पुरस्कार वापसी की मुहिम शुरू हो गई है। दूसरी ओर पंजाब में भाजपा सांसद और नेताओं पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। राजग सरकार द्वारा लाये गये तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ जारी मुहिम के बीच केंद्र सरकार ने वैकल्पिक रास्ते भी तलाशने शुरू कर दिये हैं। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के अनुसार गृहमंत्री की ओर से अचानक कुछ किसान संगठनों को वार्ता का आमंत्रण मिला है। वहीं बंद के पूर्व और बाद के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों के तेवरों से तो नहीं लगता है कि सरकार बैकफुट पर है। ऐसे में बुधवार को होने वाली छठे दौर के बातचीत के निष्कर्षों को लेकर मौजूदा हालात में सिर्फ कयास ही लगाये जा सकते हैं क्योंकि तेरह दिन से आंदोलित किसान पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते।

विदेशी मीडिया

हम क्यों नहीं समझ रहे

सर्दी ने कोविड-19 के प्रसार में तेजी ला दी है, और जैसा कि विशेषज्ञों का दावा है, इसके विविध कारणों में से एक अहम कारण है- 'सुपर स्प्रेडर्स', यानी 20 से 40 वर्ष के वे लोग, जिन्हें अपनी आजीविका के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। वे ही संक्रमण के सर्वाधिक शिकार हैं। उनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं, जिनमें कोरोना संक्रमण के मामूली लक्षण दिखे या बिल्कुल ही नहीं दिखे। ऐसे लोग उन लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, जो संवेदनशील आयु वर्ग में आते हैं। जो लोग 50 साल से ऊपर हैं, और जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए जोखिम बड़ा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के मुताबिक, इस वर्ग में मृत्यु-दर काफी ऊंची, यानी 79 प्रतिशत है। तो वह क्या पैगाम है, जो अवाम को पूरी स्पष्टता के साथ दिया जाना चाहिए? इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमिऑलजी, डिजीज कंट्रोल ऐंड रिसर्च (आईईडीसीआर) के निदेशक के मुताबिक, सुपर स्प्रेडर समूह के लिए स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन बेहद महत्वपूर्ण है। मसलन, मास्क पहनने, नियमित तौर पर साबुन से हाथ धोते रहने और दैहिक दूरी का ख्याल उनके लिए खास तौर से अहम है। मगर सार्वजनिक जगहों पर हमें इसके ठीक उलट देखने को मिलता है। बसें लोगों से ठसाठस भरी दौड़ने लगी हैं, काफी सारे लोगों ने मास्क पहनना अब बंद कर दिया है और वे अपने हाथ धोते या सैनिटाइज भी करते हैं या नहीं, यह भी संदिग्ध है। ऐसा इसीलिए है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों को लेकर लोगों में उदासीनता है। ऐसे में, स्वास्थ्य अधिकारियों को नेशनल टीवी, रेडियो, लाउडस्पीकरों और जन-जागरूकता के अन्य माध्यमों के जरिए इन दिशा-निर्देशों का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार कराना चाहिए। लोगों को जब तक इन एहतियातों की अहमियत का एहसास नहीं कराया जाएगा, तब तक इन दिशा-निर्देशों को लागू कराना कठिन है। कोरोना महामारी पहले से अधिक ताकत के साथ आज हमारे बीच है और हम स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों की अवहेलना अब और नहीं झेल सकते। संक्रमण-प्रसार के लिहाज से संवेदनशील आयु वर्ग को खास तौर से यह समझने की जरूरत है।

परंपराओं की चुनरी ओढ़े पर्यावरण

> संस्कृति और मानव विज्ञानी माग्रेट मीड जैसे शोधकर्ता सभ्यताओं को पढ़ते-पढ़ाते इस बात को अहमियत देते रहे कि हमारे जीवन के हर तौर-तरीके में कुदरत से गहरा बंधे रहना ही हमारी सभ्यता की खुदाई में हाथ आएगा। आने वाला वक्त हमें इन्हीं निशानियों से तोलेगा-मोलेगा। अद जे हमारे हाथ है, वो ये कि हम सोच पाएं कि बदलते मौसम और वक्त के मिजाज के साथ परंपराओं ने कितना निभाया

डॉ. शिप्रा माथुर

जहां बारहों मास ग्रह-उपग्रह और जल-वायु की धुरी के साथ चलते हैं, तो वहीं कहीं हमारी लोक परंपराएं भी भरी-पूरी दिखती हैं। इन्हीं की वजह से कुदरत की कलाई से जीवन का रिश्ता भी पक्का बंधा रहता है। हमारा विज्ञान केवल पंचांग में ही समाया रहता तो कितनी ही बातें हवाई रह जातीं, लेकिन उसकी कोख से पांचवीं सदी में ही शून्य ने जन्म लेकर दुनिया की अगुवाई की और 21वीं सदी में भी यही टटोलने-परखने की चेतना आंगन-आंगन की रंगोली बनी रही। मनमानस में बसे रहकर हमारी परंपराओं ने अपनी खास बुनावट को झोपड़े मेंग चूल्हे के बगल में, खलिहानों में बहते पसीने की तर-बतर में और ताल-बावड़ियों की छपछपाहट के साथ तपते, भीगते, नाचते, गाते भरपूर जिया भी है और चुभते वक्त पर पार भी पाई है। रीत-रिवाज की थाप और लोक धुनों ने इंसानी समाज को जिस तरह चलना सिखाया है, उसमें सबसे पुरजोर हिस्सा कुदरत के संग जुड़े अहसासात का ही रहा है।

संस्कृति और मानव विज्ञानी माग्रेट मीड जैसे शोधकर्ता सभ्यताओं को पढ़ते-पढ़ाते इस बात को अहमियत देते रहे कि हमारे जीवन के हर तौर-तरीके में कुदरत से गहरा बंधे रहना ही हमारी सभ्यता की खुदाई में हाथ आएगा। आने वाला वक्त हमें इन्हीं निशानियों से तोलेगा-मोलेगा। आज जो हमारे हाथ हैग वो ये कि हम सोच पाएं कि बदलते मौसम और वक्त के मिजाज के साथ परंपराओं ने कितना निभाया। हमारे यहां साल का पहला महीना यानी चैत में जीवन की कोपलें फूटती हैंग जौ, चना, गेहूं, सरसों पकने लगती हैं और नवरात्रि के नौ दिन हम उसी जीवन के साथ अपनी लय में रहते हुए छोटी बच्चियों को भी पूजते हैं। जब कोविड के धक्के ने हमारी दखल की हदें तय कर दीं, तो कलकल और चहचहाहट को सुनकर, उन्हें अपने अक्स की तरह सामने देखकर हम नींद से जाग उठे। हमें मालूम है कि हम अब लौट नहीं सकते, लौटना भी नहीं चाहिए वहां जहां हम खुद की ही बात सुनने और जी भर कर देखने के काबिल नहीं रहे थे। पूनम से अमावस की घटत-बढ़त के बीच तारीखें खुद कुछ नहीं कह पातीं। जब हवाग बादल, बारिश, पंछी, जीव और जंगल तारीख की पोटली में भरे पल भी हिसाब रखना भूल जाते हैं, तो इंसान बस उन्हें अपने जेहन में दर्ज करता चलता है। यहीं से उसके खयालों में इन सबकी फिक्र आती है, क्योंकि उसका अपना वजूद भी इन्हीं से खुशरंग है।

भरे-पूरे इलाके हों या उजाड़, कैनवास पर हल्के या चटख रंग तो कुदरत के ही बिखरते हैं, तभी दुनियावी तस्वीर पूरी हो पाती है। चैत्र की करवट से बैसाख की शोखी के बीच जब राजस्थान के सूखे इलाकों में आखा तीज का त्योहार मनता है तो खेजड़ी का पूजन होता है। दुनिया के और इलाकों में अपने सब्र के लिए मशहूर है खेजड़ी। इसकी उजाड़ पर आमादा एक राजा के फरमान के खिलाफ खड़े होकर जब चार सदी पहले खेजड़ली गांव में अमृता देवी ने मोर्चा संभाला था, तो फिर यकीन गहरा हुआ कि औरतों ने दुनिया को किस कदर संभाले रखा है। 'सर सांटेग रूख रहे, तो भी सस्तो जाण' कहकर अमृता तो कुर्बान हुई, मगर पीछे-पीछे उनकी तीन बेटियों और 363 आदिवासियों के बलिदान के साथ खेजड़ी बचाने के लिए सिर कटाना ऐसी मिसाल बना कि उसके बराबर दुनिया में कोई कहानी नहीं आज भी। औरतों के हाथों कुदरत की संभाल की तहजीब को जब 'ईको-फेमिनिज्म' की तरह बांचा गया, तब मां, दादी, बहन, भाभी, ननद के आगे-पीछे घूमती घर की दुनिया में सूर्य नमन और पीपल-कुंआ पूजन की परंपरा नजर भर कर देखने में आई। छठ पूजन में सूरज और उसकी बहन छठ मैया के बीच इतना लाड़-प्यार बरसता है कि पूरा साल भरा पूरा सा लगता है। साझी हिस्सेदारी वाली गोचर जमीनों पर लोक देवी-देवताओं के नाम पर 'वणी' और 'ओरण' बनाकर जमीन और मिट्टी में पल रहे पौधों और जीवों के बंध और नमी का खयाल रखा जाता है।

देहाती जन-जीवन में मिट्टी से थपे चौके में चूने और गेरू से रंगे मांडणों में कुदरत से हमारे रिश्ते की छाप हो या फिर सफेद दीवारों पर हल्दी की थपकी के छापे, गांवों ने ही भारत की संभाल की है। यहां बसी रीतियों की बदौलत ही जल-हवा-मिट्टी, पंछी और जीवों का सांझ और सवेरा साथ-साथ होता है और मौसम के मुताबिक खान-पान, आन और दान की रीत होती है। संक्रांति में तिल-गुड़, सावन में शिव का बेलपत्र-जल, देवों के सोने के चार महीनों के दौरान पुरखों का मानग बसंत पंचमी में पीली सरसों की बिछावन और गाय-बछड़ों के लाड़ के लिए गोपाष्टमी जैसे अनगिनत मौके हैं हमारी परम्परा में जो हमारे और नीली-हरी धरती के बीच चुंबक सरीखे हैं। बेटियों की पैदाइश पर पौधे लगाने जैसी नई परंपराओं ने जन्म लेकर दकियानूसी सोच की सफाई भी की है। ऐसी अनगिनत जड़ी-बूटियां जो हमारे लिए मरहम हैं, पहाड़ों और जंगलों की बेपरवाही से घरों की बंदिशों में समा रही हैं। सरकारों ने इसे 'पोषण वाटिका' की शक्ल देकर इंसान और पेड़ों के रिश्तों की सजावट ही की है, जिसमें खासकर मां-बच्चे की फिक्र शामिल है। रिश्तों को अहमियत देने की हमारी फितरत परंपराओं की ही वजह से है। यही दूरियों को भरने का काम करती हैं। दूरियों का जिक्र छिड़ते ही लोक परंपराओं को चूनर की तरह लपेट कर रखने वाली देहाती औरतें हमें ये कहकर झिड़क देती हैं कि क्या त्योहार भी देस-विदेस का होता है। जिस रंग को ओढ़ लो वही तो अपना है और वहीं अपनापन है।

पानी का मोल जानने वाले इलाकों में सावन के लहरिये की सज-धज के साथ मिट्टी की दाबू छपाई वाले कपड़े नए दौर के चलन में दूरदराज पहुंच रहे हैं, तो वहां भी अब कुदरत के तौर-तरीकों को सहेजने वाली रंगाई-छपाई की पूछ है। खेती किसानी में रमी आशा जी को सरकार के नरेगा के काम में तालाबों से मिट्टी खुदवाने का काम उसी तरह लगता हैग जिस तरह कुंओं-तालाबों की मिट्टी साफ करके गांव का हर घर अपनी मेहनत का दान किया करता था। साथ उठना, खाना, कहना, सुनना, गाना-बजाना सब इसी बहाने से होता रहा है, जिसकी कसक अब गांव-शहरों को नजदीक ले आई है। जो गांव शहर होने की फिराक में थे, अब उनकी वकत बढ़ी हैग तो सिर्फ इसलिए कि वहां बसी सादगी, साफगोई और आबोहवा की ही दुनिया को दरकार है। यह आत्मनिर्भरता की आस के बीच सरकारों के सरोकारों का भरा पूरा हिस्सा होना चाहिए। पूरब की कोसी से मध्य की नर्मदा-शिप्रा, पश्चिम के मीठे-खारे तालाब बावड़ियों से लेकर दक्खिन की कृष्ण-गोदावरी और उत्तर की गंगा-यमुना, सबके सब धरती में दबे बीजों को मिट्टी चीरने का हौसला देकर जीवन की बालू मिट्टी के पोर-पोर को भिगाए रखती हैं तो हमें भी अपनी परम्पराओं के पांव फिर छूकर पर्यावरण से हमारे इश्क-मोहब्बत का खुलकर इजहार करने की सलाहियत बरतनी ही चाहिए।

नेपाल

सत्ताधीशों की विफलता से फिर राजशाही की मांग

विष्णुगुप्त

आश्चर्यजनक ढंग से पिछले दो माह से नेपाल के अंदर राजशाही की मांग जोर पकड़ रही है। राजधानी ही नहीं बल्कि छोटे से लेकर बड़े शहरों में भी राजशाही के पक्ष में प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शन में कम्युनिस्ट तानाशाही के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले वे युवा हैं जो सपनों के बिखरने और संस्कृति संकट से क्षुब्ध हैं। राजशाही की वापसी का समर्थन करने वाली नेपाल प्रजातंत्र पार्टी पहले की अपेक्षा ज्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है।

मार्क्सवादी विचारधारा में पूंजी के अतिरंजित विरोध का आग्रह है। पूरा ध्यान मजदूरों के हितों पर केन्द्रित है। सवाल उठाया जाता है जब मजदूर हित ही सर्वोपरि होंगे तब कोई पूंजी निवेश करेगा क्यों? तो फिर कोई उद्योग धंधा विकसित कैसे होगा? अगर कोई उद्योग धंधा विकसित नहीं होगा तो फिर मजदूरों को काम कहां मिलेगा? यही कारण है कि सोवियत संघ से लेकर चेकोस्लोवाकिया तक जहां-जहां पर कम्युनिस्ट तानाशाही थी वहां-वहां पर प्रतिस्पर्धा के गौण होने के बाद विखंडन की प्रक्रिया सुनिश्चित हुई, जनता ने कम्युनिस्ट तानाशाहियों को उखाड़ फेंकने में ही अपनी भलाई समझी। चीन जरूर अपने आप को जनता का कोपभाजन बनने से रोक पाया पर चीन ने मजदूर हित को ही गौण कर दिया और पूंजीवाद से अपना हित सुरक्षित कर दिया।

आधुनिक समय में जहां-जहां भी कम्युनिस्ट सरकारें आयीं वहां-वहां अराजकता, अर्थव्यवस्था विध्वंस और राजनीतिक हिंसा की बाढ़ आयी और लोकइच्छाएं या दमन हुईं या फिर कम्युनिस्ट तानाशाही कायम करने के लिए लोकइच्छाओं का विध्वंस कर दिया गया। दुनिया में दो ऐसे देश हैं जो उपर्युक्त सच्चाई पर खरे उतरते हैं। एक उदाहरण नेपाल का है और दूसरा उदाहरण अमेरिकी देश वेनेजुएला का है। वेनेजुएला में कम्युनिस्ट तानाशाही का दुष्परिणाम यह हुआ कि वेनेजुएला का भी वही हाल हुआ जो सोवियत संघ का हुआ था।

नेपाल में माओवाद को मिली सफलता से दुनिया में फिर विमर्श हुआ था कि कार्ल मार्क्स का जमाना लौट गया। माओवादी भी नेपाल को एक आदर्श कम्युनिस्ट देश में तबदील करने की प्राथमिकता रखते थे। 240 साल से भी अधिक समय की राजशाही का नेपाल में अंत हुआ और माओवादी व अन्य कम्युनिस्टों ने मिलकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनायी। नेपाली कांग्रेस की अराजकता और निरंकशुता के विकल्प के तौर पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता मिल गयी। पुराने मार्क्सवादी ओली प्रधानमंत्री बन गये। पूंजी निवेश और संस्कृति के प्रश्न पर कम्युनिस्ट अपने आप को बदल नहीं सके। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली और माओवादी नेता प्रंचड नेपाल के अंतर्विरोध के प्रतीक बन गये। नेपाल में संवैधानिक तौर पर राजशाही समर्थक सोच का दमन पहले ही कर दिया गया था और धर्मनिरपेक्षता को प्रधान बना दिया गया था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि नेपाल आज भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के केन्द्र में स्थापित हो गया है।

एक बार फिर पिछले दो माह से नेपाल के अंदर राजशाही की मांग जोर पकड़ रही है। काठमांडू ही नहीं बल्कि छोटे-बड़े शहरों में भी राजशाही के पक्ष में जमकर प्रदर्शन हुए हैं पर विचार करने वाली बात यह है कि प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले अधिकतर नयी पीढ़ी के लोग हैं, जिसमें राजशाही का समर्थन करने वाली नेपाल प्रजातंत्र पार्टी की पकड़ मजबूत होती प्रतीत हुई है। यह यक्ष प्रश्न है कि क्या कम्युनिस्ट सरकार को पराजित कर नेपाल में एक बार राजशाही की स्थापना हो सकती है? अगर नेपाल में एक बार फिर राजशाही कायम हुई तो फिर नेपाल के लोकतंत्र का क्या स्वरूप होगा? इधर कई ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, जिससे नेपाल के लोगों के मन में अपनी सुरक्षा और आयातित संस्कृति के खतरे को लेकर चिंता आगे बढ़ी है। कभी शांत रहने वाला नेपाल आज आयातित संस्कृति की हिंसा से दग्ध है। उधर पश्चिमी देशों की मिशनरियां नेपाल की गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा कर धर्मांतरण का खेल, खेल रही है। मौजूदा नेपाली नेतृत्व अपनी खुशफहमी छोड़ दे तो फिर नेपाल में राजशाही की वापसी रुक सकती है। लेकिन उम्मीद नहीं है कि उनकी यह खुशफहमी टूटने वाली है। नेपाल में अभी दो ही राष्ट्रीय मुख्यधारा की पार्टियां हैं। एक नेपाली कांग्रेस और दूसरी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाली कांग्रेस को आम जनता पहले ही खारिज कर चुकी है पर अभी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है। अगर दोनों पार्टियां जनता के बीच अलोकप्रिय होंगी, असफल होंगी तो फिर राजशाही पक्षधर प्रजातांत्रिक पार्टी के विस्तार को कौन रोक सकता है?

मौद्रिक समीक्षा

आर्थिकी में तेज सुधार की आस

सतीश सिंह

वर्ष 2020 की आखिरी मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर को 4 प्रतिशत पर यथावत रखा गया। रिवर्स रेपो दर को 3.35 प्रतिशत और स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ) व बैंक दर को भी 4.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। मौद्रिक नीति समिति के सभी सदस्यों ने मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को देखते हुए नीतिगत दर को यथावत रखने के पक्ष में निर्णय किया। चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत गिरावट का अनुमान है। पहले रिजर्व बैंक ने 9.5 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान लगाया था। दो महीने के अंदर गिरावट में 2 प्रतिशत कमी आने का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी वृद्धि दर तीसरी तिमाही में 0.1 प्रतिशत के साथ सकारात्मक दायरे में लौट आने की आस है, जबकि चौथी तिमाही में इसमें 0.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति तीसरी तिमाही में 6.8 प्रतिशत, चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। वैसेग भारतीय रिजर्व बैंक ने सतदयों में महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद जताई हैग जिसका कारण रबी के फसलों का उत्पादन बंपर होने का अनुमान है। रबी की बुआई का रकबा बढ़॰ने से 2020-21 में कृषि उत्पादन में इजाफा होगाग जिससे श्रमिकों की मांग भी बढ़ेगी। केंद्रीय बैंक का मानना है कि आपूतत पर महंगाई का दबाव हैग लेकिन आतथक गतिविधियों में तेजी आने और मानसून के ठीक रहने से महंगाई नियंत्रण में आ जाएगी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कॉरपोरेट आय में इजाफे से पता चलता है कि मांग में सुधार हो रहा है, जिससे मुनाफे में भी बढ़ोतरी हो रही है। रिजर्व बैंक ने कहा कि वित्तीय बाजार व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि वाणिज्यिक व सहकारी बैंक 2019-20 का मुनाफा अपने पास ही रखेंगे और वित्त वर्ष के लिए लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे। ऐसा करने से बैंक की पूंजी में बढ़ोतरी होगी और वे ज्यादा से ज्यादा ऋण वितरण का कार्य कर सकेंगे। तीसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आतथक अनिश्चितता का भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में आतथक गतिविधियों में सुधार देखा जा रहा है। अक्टूबर महीने में कारों, दोपहिया और तिपहिया के साथ-साथ ट्रैक्टरों की बिक्री भी बढ़ी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है और 2020-21 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अक्टूबर महीने के लिए क्षेत्रवार ऋण वृद्धि का आंकड़ा जारी किया है, जिसके अनुसार उद्योग को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि दर में इजाफा हुआ है। हालांकि यह वृद्धि पिछले साल के सितंबर महीने से कम हैग लेकिन तालाबंदी के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए इन आंकड़ों को उत्साहजनक माना जा सकता है। सबसे अधिक ऋण वृद्धि वैयक्तिक ऋण क्षेत्र में हुआ है। खाद्य तेल पैकेजिंग एफएमसीजी फार्मा सीमेंट स्टील, कंज्यूमर ड्यूरेबल आदि क्षेत्रों में भी तेज वृद्धि हुई है। सभी अनुसूचित व्यवसायिक बैंक की वृद्धिशील ऋण वृद्धि नवंबर महीने में सकारात्मक रही है। रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को काल और नोटिस बाजार में कारोबार की अनुमति देने से उन्हें नकदी का बेहतर प्रबंधन करने का अवसर मिलेगा। अभी उन्हें अक्सर नकदी की कमी का सामना करना पड़ता है। बीते सालों आईएल एंड एफएस एवं दीवान हाउसिंग लिमिटेड एनबीएफसी कंपनियों में आए संकट की वजह से एनबीएफसी की साख को भारी धक्का लगा था जिसको एक महत्वपूर्ण कारण कमजोर ऑडिट की व्यवस्था का होना था। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक समीक्षा में रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को एनबीएफसी के लिए भी अनिवार्य कर दिया है।

कोरोना महामारी के साये में रिजर्व बैंक का ध्यान फिलवक्त जीडीपी की दर बढ़ाने पर है। इसी को ध्वनित करते हुए केंद्रीय बैंक सुधारात्मक कदम उठा रहा है। भले ही रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कटौती नहीं की हैग लेकिन जरूरत पड़ने पर वह ऐसा कर सकता है। रिजर्व बैंक का मानना है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में उम्मीद से ज्यादा तेजी से जीडीपी वृद्धि दर में तेजी आएगी। मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखना रिजर्व बैंक द्वारा उठाया गया समीचीन कदम है।

शेयर बाजार में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड 46,103 पर बंद हुआ सेंसेक्स

मुंबई। देश का शेयर बाजार बुधवार को जोरदार लिवाली से गुलजार रहा। सेंसेक्स बीते सत्र से 495 अंकों की उछाल के साथ 46,100 के ऊपर रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 136 अंकों की तेजी के साथ 13,529 पर ठहरा। इससे पहले सेंसेक्स कारोबार के दौरान 46,164.10 तक उछला, जोकि सर्वाधिक ऊंचा स्तर है और निफ्टी भी 13,548.90 तक चढ़ा। कोरोना वैक्सीन की प्रगति और विदेशी बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है और प्रमुख संवेदी सूचकांक बुलंदियों को छू रहे हैं। सेंसेक्स बीते सत्र से 494.99 अंकों यानी 1.09 फीसदी की तेजी के साथ 46,103.50 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 136.15 अंकों यानी 1.02 फीसदी की तेजी के साथ 13,529.10 पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बीते सत्र के मुकाबले 282.53 अंकों की बढ़त के साथ 45,891.04 पर खुला और दिनभर के कारोबार के दौरान 46,164.10 तक चढ़ा, जबकि इसका निचला स्तर 45,792.01 रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी बीते सत्र से 65.15 अंकों की बढ़त के साथ 13,458.10 पर खुला और दिनभर के कारोबार के दौरान 13,548.90 तक उछला, जबकि इसका निचला स्तर 13,449.60 रहा। बीएसई मिडकैप सूचकांक बीते सत्र से 70.89 अंकों यानी 0.40 फीसदी की तेजी के साथ 17,596.17 पर बंद हुआ और निफ्टी 85.84 अंकों यानी 0.49 फीसदी की तेजी के साथ 17,577.45 पर ठहरा। बीएसई के 30 शेयरों में से 20 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 10 शेयरों में गिरावट रही। सबसे तेजी वाले पांच शेयरों में एशियन पेंट (3.27 फीसदी), कोटक बैंक (2.67 फीसदी), एसिक्स बैंक (2.19 फीसदी), एचडीएफसी बैंक (2.15 फीसदी) और इन्फोसिस (1.85 फीसदी) शामिल रहे। सेंसेक्स के गिरावट वाले पांच शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट (1.29 फीसदी), टाटा स्टील (0.79 फीसदी), मारुति (0.70 फीसदी), बजाज ऑटो (0.61 फीसदी) और एसबीआईएन (0.59 फीसदी) शामिल रहे। बीएसई के 19 सेक्टरों में से 17 में तेजी रही, जबकि दो सेक्टरों के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी वाले पांच सेक्टरों के सूचकांकों में बैंक इंडेक्स (1.47 फीसदी), एनर्जी (1.46 फीसदी), रियल्टी (1.39 फीसदी), वित्त (1.04 फीसदी) और आईटी (1.03 फीसदी) शामिल रहे। जबकि पावर (0.25 फीसदी) और आधारभूत सामग्री (0.13 फीसदी) गिरावट के साथ बंद हुए।

सिस्को अधिकारी ने कहा- 5G की पेशकश बाजार में जोरदार छलांग लगाने का अभूतपूर्व मौका

नई दिल्ली: सिस्को के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अगली पीढ़ी की 5जी प्रौद्योगिकी में वृद्धि के अभूतपूर्व अवसर हैं और इससे बैंडविड्थ, नए औद्योगिक उपयोग के मामलों और उद्यम बाजार की मांग में तेजी आएगी तथा सेवाप्रदाता 5जी नेटवर्क में निवेश के लिए प्रेरित होंगे। सिस्को इंडिया और सार्क के प्रबंध निदेशक (सेवा प्रदाता) आनंद भास्कर ने कहा कि भारत के डिजिटल रूपांतरण के कई स्तर हैं, जिसमें बैंडविड्थ की जरूरत, उद्योगों के लिए उपयोग के नए मामले और 5जी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा शामिल है। उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के आभासी सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ''5जी ने हमारे लिए छलांग लगाने का एक अभूतपूर्व अवसर तैयार किया है। उन्होंने आगे कहा कि अध्ययन बताते हैं कि करीब 10-12 प्रतिशत भारतीय मोबाइल ग्राहक 5जी मोबाइल सेवाओं का खर्च उठा सकते हैं, जिससे प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, ''यह अच्छी खबर है एक अरब मोबाइल ग्राहकों में यदि 10 करोड़ से अधिक 5जी सेवा का उपयोग कर सकते हैं तो यह दूरसंचार कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर है।

जनवरी से बदल जाएंगे GST रिटर्न के ये नियम, छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली:

जीएसटी सिस्टम को और सरल करते हुए सरकार सेल्स रिटर्न दाखिल करने के मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी में है। सालाना पांच करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से साल के दौरान महज चार बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। राजस्व विभाग के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

नया नियम लागू होने के बाद

इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न (**GSTR-3B**) दाखिल करने होते हैं। इसके अलावा 4 जीएसटीआर-1 (4 **GSTR-1**) भरना होता है। नया नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 जीएसटीआर-3बी और 4 जीएसटीआर-1 (**GSTR-1**) रिटर्न भरना होगा।

94 लाख टैक्सपेयर्स पर होगा असर

सूत्रों ने बताया कि टैक्स की मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल (**QRMP**) करने की योजना का असर करीब 94 लाख टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा। यह जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स का लगभग 92% है यानी इस योजना जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों की बड़ी संख्या को फायदा होगा। इस प्रकार अगले साल जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में चार जीएसटीआर-3बी और चार जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने होंगे।

छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत

सूत्रों ने बताया कि इस योजना को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उपलब्ध कराने में भी लागू किया जाएगा। यह केवल रिपोर्ट किए जाने वाले बिलों को लेकर होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इनवॉयस दाखिल करने की सुविधा (आईआईएफ) का विकल्प भी दिया जाएगा। आईआईएफ सुविधा के तहत इस योजना का लाभ उठाने वाले छोटे कारोबारी तिमाही के पहले और दूसरे महीने में अपने बिल अपलोड कर पाएंगे।

स्टील की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, नए साल में कार-बाइक हो सकते हैं महंगे

बिजनेस डेस्क: स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी होने से नए साल में साइकिल, बाइक और कारें महंगी हो सकती हैं। इनपुट लागत में वृद्धि को देखते हुए ऑटो सेक्टर को इस का बोझ ग्राहकों की जेब पर डालना पड़ सकता है। स्टील की कीमतें बढ़ने से न केवल ऑटो सेक्टर बल्कि आवासीय फ्लैट बना रहे बिल्डरों और निजी होम बिल्डर्स के साथ-साथ सरकारी परियोजना के ठेकेदार भी प्रभावित होंगे। सूत्रों के अनुसार, स्टील कंपनियों ने दिसंबर में दूसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी की है। मौजूदा समय में कीमतों में 1,500 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले पिछले सप्ताह स्टील की कीमतों में लगभग 2,500 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई थी। इस तरह दिसंबर में स्टील 4,000 रुपए प्रति टन महंगा हुआ। स्टील ऑटो विनिर्माण में एक प्रमुख इनपुट है और इस्पात उद्योग की महत्वपूर्ण मांग में इसका अहम योगदान है। भारत स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि, आयात के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले स्टील की मांग अभी भी पूरी होती है। स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी उन ऑटो कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका हैं जिनकी मांग कोरोना कल के दौरान पहले से ही कमजोर है।

देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम उद्योगों का है, सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा सकती: पवन गोयनका

नई दिल्ली: विनिर्माण क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का दायित्व सरकार का नहीं बल्कि उद्योग जगत का है। सरकार यदि कुछ कर सकती है तो वह बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी पवन गोयनका ने मंगलवार को यह बात कही। गोयनका भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्योग और सरकार को एक टीम बनकर मिशन की तरह यह काम करना होगा। ताकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए विभिन्न कारोबारों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि सस्ते श्रम और कच्चे माल की प्रचुरता जैसी अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद देश विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। गोयनका ने कहा, ''आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य है वह हमारे (उद्योग) लिए है ना कि सरकार के लिए। सरकार सिर्फ सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। हम क्या करने जा रहे हैं? मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि क्या अगले 12 महीने में मैं अपनी कंपनी के शेयर का मूल्य देखने जा रहा हूं या प्रौद्योगिकी में निवेश करने जा रहा हूं। क्या हमारे अंदर देश को आत्मनिर्भर बनाने की भूख है?'' उन्होंने कहा कि यह उद्योग जगत पर निर्भर करता है कि विनिर्माण और आत्मनिर्भरता के संदर्भ में हम देश को आगे रखते हैं या सरकार से अपने खुदके फायदे की चाहत रखते हैं।

5G पर मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल की अलग-अलग राय

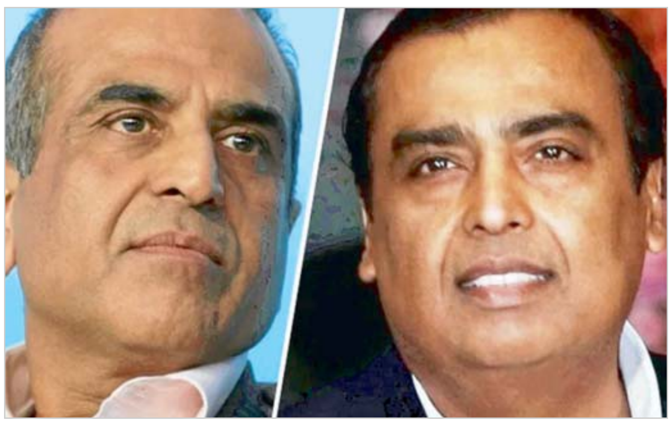

बिजनेस डेस्क:

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील मित्तल ने भारत में 5त्र टाइमलाइन पर अपने अलग-अलग विचार पेश किए हैं। जहां मुकेश अंबानी ने अगले साल यानी 2021 की दूसरी छमाही में 5जी सर्विसेज शुरू करने के संकेत दिए हैं वहीं, जियो की प्रतिद्वंदी एयरटेल के चेयरपर्सन सुनील मित्तल की सोच थोड़ी अलग है। उन्होंने कहा कि कंपनी अगले दो-तीन साल में अगली पीढ़ी की 5जी सर्विसेज मोबाइल ब्रॉडबैंड क्षेत्र की अगुवाई करेगी। सुनील मित्तल ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब हाल ही में मासिक कनेक्शन के मामले में एयरटेल ने रिलायंस जियो को पीछे छोड़ा है। रिलायंस जियो की लॉन्चिंग के करीब 4 साल बाद पहली बार एयरटेल को ये सफलता मिली है। ऐसे में रिलायंस जियो की टेंशन बढ़ गई है।

मुकेश अंबानी ने क्या कहा

मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो देश में 5जी क्रांति की अगुवाई करेगी। उन्होंने कहा, ''मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जियो 2021 की दूसरी छमाही में देश में 5जी क्रांति की अगुवाई करेगी। जियो का 5जी देश में विकसित नेटवर्क, हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी उपकरणों पर टिका होगा। 'जियो की 5जी सेवाएं आपके प्रेरित करने वाले आत्मनिर्भर भारत के दृष्टकोण के अनुरूप होंगी।' अंबानी ने कहा कि देश में आज भी 30 करोड़ ग्राहक 2जी में 'फंसे' है और उन्हें स्मार्टफोन में लाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है। स्मार्टफोन के जरिए ये ग्राहक भी डिजिटल लेनदेन में सक्षम हो सकेंगे।

सुनील मित्तल ने क्या कहा

मित्तल ने कहा कि अब जबकि दुनिया 5जी के लिए तैयार हो रही है, उपकरणों के दाम नीचे आने लगे हैं। अब उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मुझे लगता है कि भारत दो-तीन साल में वैश्विक स्तर पर 5जी मानकों तथा पारिस्थितिकी तंत्र में हुए निवेश का लाभ उठाने की स्थिति में होगा।

कुल मोबाइल कनेक्शनों की संख्या के मामले में रिलायंस जियो 40.41 करोड़ ग्राहकों के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है। वहीं भारती एयरटेल 32.66 करोड़ कनेक्शनों के साथ दूसरे स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार सितंबर, 2020 में भारती एयरटेल ने 37.7 लाख नए कनेक्शन जोड़े हैं। रिलायंस जियो ने 14.6 लाख नए ग्राहक बनाए हैं।

मोदी कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को दी मंजूरी, 58.5 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

बिजनेस डेस्क:

देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। इस योजना के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में 1,584 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, पूरी योजना में साल 2020 से 2023 की अवधि के दौरान कुल 22,810 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना से 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

सरकार देगी 24% ईपीएफ में योगदान

इस योजना के तहत केंद्र सरकार एक अक्टूबर 2020 को या उसके बाद और 30 जून, 2021 तक शामिल सभी नए कर्मचारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। बयान में कहा गया, ''जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 कर्मचारी हैं वहां केन्द्र सरकार दो वर्ष की अवधि के लिए 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान और 12 प्रतिशत नियोक्ता योगदान (दोनों) वेतन भत्तों का 24 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान देगी।%% इसके मुताबिक जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं वहां केन्द्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफ में केवल 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान देगी।

किस कर्मचारी को होगा फायदा

कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है और वह किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहा था जो एक अक्टूबर 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल एकाउंट नंबर या ईपीएफ सदस्य खाता नंबर नहीं था तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा। कोई भी ईपीएफ सदस्य जिसके पास यूनिवर्सल एकाउंट नंबर है और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है और यदि उसने कोविड महामारी के दौरान इस वर्ष मार्च से सितंबर के बीच की अवधि में अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे ईपीएफ के दायरे में आने वाले किसी रोजगार प्रदाता संस्थान में सितंबर तक रोजगार नहीं मिला है तो वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।

बयान में कहा गया कि सदस्यों के आधार संख्या से जुड़े खाते में ईपीएफओ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा। इस योजना के लिए ईपीएफओ एक सॉफ्टवेयर को विकसित करेगा और एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। ईपीएफओ यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तरीका अपनाएगा कि एबीआरवाई और ईपीएफओ द्वारा लागू की गई किसी अन्य योजना के लाभ आपस में परस्पर व्याप्त (ओवरलैपिंग) नहीं हुए हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन लक्ष्य 2030 को पाने के लिए 12.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की जरूरत: अध्ययन

नई दिल्ली:

भारत यदि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो इसका ईवी बाजार करीब 14.42 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। हालांकि, इसके लिए इसे लगभग 12.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। एक अध्ययन में यह कहा गया है। सीईईडब्ल्यू सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस (सीईईडब्ल्यू-सीईएफ) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, मार्च 2020 के अंत तक भारत में पंजीकृत ईवी की कुल संख्या केवल पांच लाख थी। अध्ययन के अनुसार, सभी वाहन खंडों में कुल ईवी बिक्री 2030 तक 10 करोड़ से अधिक हो सकती है, जो बाजार के मौजूदा आकार का 200 गुना होगी।

2030 तक 80% ईवी वाहनों की होगी बिक्री

अध्ययन में कहा गया है कि भारत की ईवी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए वित्त वर्ष 2030 तक 158 गीगावॉट की अनुमानित वार्षिक बैटरी क्षमता की आवश्यकता होगी। इससे घरेलू निर्माताओं के लिए बड़े पैमाने पर बाजार में अवसर उपलब्ध होंगे। अध्ययन में नीति आयोग के लक्ष्य का हवाला देते हुए कहा गया कि भारत के ईवी 2030 लक्ष्य के अनुसार, 2030 तक सभी वाणिज्यिक कारों की 70 प्रतिशत, निजी कारों की 30 प्रतिशत, बसों की 40 प्रतिशत और दोपहिया व तिपहिया वाहनों की 80 प्रतिशत बिक्री ईवी की होगी। अध्ययन में कहा गया, ''यदि भारत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो इससे देश का ईवी बाजार करीब 14.42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

29 लाख से अधिक चार्जिंग प्वायंट की होगी जरूरत

सीईईडब्ल्यू-सीईएफ के वरिष्ठ विश्लेषक वैभव प्रताप सिंह ने कहा, ''मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), बैटरी निर्माताओं, चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों और अंतिम छोर के उपभोक्ताओं के लिए पूंजी की उपलब्धता और किफायती कीमत महत्वपूर्ण होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लगातार नीतिगत समर्थन भी महत्वपूर्ण होगा।

वैभव प्रताप सिंह इस अध्ययन के मुख्य लेखक भी हैं। अध्ययन में कहा गया कि भारत को वित्त वर्ष 2030 तक घरों में स्थित निजी चार्जिंग प्वायंट के अतिरिक्त 29 लाख से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग प्वायंट की जरूरत होगी।

कोविड-19 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों में 38 अरब डॉलर का निवेश आया- कांत

हैदराबाद:

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि पिछले छह महीने में देश की प्रौद्योगिकी कंपनियों में 38 अरब डॉलर का निवेश आया है। यह निवेश ऐसे समय आया जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामरी से जूझ रही है। तीन दिवसीय टीआईई ग्लोबल समिट (टीजीएस) में कांत ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप परिवेश में 55,000 से अधिक स्टार्टअप का गठन हुआ जिन्होंने पिछले पांच साल में 60 अरब डॉलर का वित्त पोषण प्राप्त किया। 'ऑनलाइन' आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ''जब दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, भारत ने पिछले पांच या छह महीनों में 38 अरब डॉलर से अधिक प्रौद्योगिकी निवेश प्राप्त किया है। यह भारत की खासकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्षमता को बताता है।' एक सवाल के जवाब में कांत ने कहा ककि कृत्रिम मेधा (एआई) भारत के लिए एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है। इस उभरती प्रौद्योगिकी से 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 957 अरब डॉलर और आएंगे। डेटा सुरक्षा के सवाल पर उनहोंने कहा कि तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में हमें न केवल मजबूत डेटा सुरक्षा चाहिए बल्कि डेटा सशक्तिकरण की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में 65 करोड़ के करीब इंटरनेट का उपयोग करने वाले हैं। हर तीन सैकिंड में एक नया कनेक्शन जुड़ता है। वहीं 50 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के बीच यह दुनिया में डेटा का सबसे अधिक उपभोग करता है।

आरबीआई ने इस बैंक का किया लाइसेंस रद्द, जानें बैंक के डिपॉजिटर्स का क्या होगा

बिजनेस डेस्क:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के कराड में संकटग्रस्त 'कराड जनता सहकारी बैंक' का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की है। बता दें कि इससे पहले नवंबर 2017 से ही कराड जनता सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई थीं। आरबीआई ने कहा कि लाइसेंस रद्द होने के बाद अब बैंक पूरी तरह से बंद हो जाएगा।

इस नियम के तहत रद्द किया गया बैंक का लाइसेंस

रिजर्व बैंक ने बैंक का लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी दिया था। आरबीआई के मुताबिक, सेक्शन-22 के नियमों के मुताबिक बैंक के पास अब पूंजी और कमाई की कोई गुंजाइश नहीं है। कराड बैंक बैंकिंग रेगुलेशन, 1949 के सेक्शन-56 के पैमानों पर खरा नहीं उतरा। अब बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। मौजूदा स्थिति में बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा। इसी वजह से उसका लाइसेंस रद्द किया गया है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी 99 फीसदी जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी। डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 (**DICGC Act** 1961) के तहत डिपॉजिटर्स को बैंक के लिक्विडेशन पर 5 लाख तक की रकम वापस मिल जाएगी। इसलिए 99 फीसदी डिपॉजिटर्स को बैंक में जमा अपनी पूरी पूंजी वापस मिल जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के लाइसेंस को रद्द करने और लिक्विडेशन की कार्यवाही शुरू करने के साथ ही जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला 7 दिसंबर के कामकाज के बाद प्रभावी हो गया है। इसके प्रभावी होने के साथ बैंक अब बैंकिंग से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं कर सकता है।

फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों के नियमन की याचिका: अदालत ने केंद्र, RBI से मांगा जवाब

बिजनेस डेस्क:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में फेसबुक, गूगल और अमेजन जैसी वित्तीय प्रौद्योगिकी (टेकफिन) कंपनियों के संचालन को विनियमित करने के लिए एक विस्तृत कानूनी ढांचे का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ईआरडीएआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से बुधवार को जवाब मांगा। एक अर्थशास्त्री द्वारा दायर याचिका के अनुसार, ये टेकफिन कंपनियां दरअसल प्रौद्योगिकी, दूरसंचार या ई-वाणिज्य कंपनियां हैं, जो अब वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिये वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं और उनका विनियमन करने की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने वित्त एवं विधि मंत्रालयों को नोटिस जारी किए। इसके अलावा पीठ ने आरबीआई, एनपीसीआई, आईआरडीएआई, सेबी और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को भी नोटिस जारी कर उनसे रेशमी पी भास्करन की याचिका पर अपना रुख बताने को कहा। भास्करन ने अधिवक्ता दीपक प्रकाश के माध्यम से दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि भारतीय वित्तीय नियामकों के त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण ने टेकफिन कंपनियों को अनियंत्रित संचालन की छूट दी है। याचिका में दावा किया गया है कि इससे देश की वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भारत के खिलाफ शुरुआती टेस्ट मैच से पहले खिलाड़ियों के चोटिल होने से परेशानी में ऑस्ट्रेलिया

मेलबर्न। (एजेंसी)।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने कहा कि भारत के खिलाफ शुरुआती टेस्ट से पहले खिलाड़ियों के चोटिल होने से परेशानी का सामना कर रही उनकी टीम के लिए अनुभवी शॉन मार्श सलामी बल्लेबाज के विकल्प हो सकते है।दोनों देशों के बीच चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 17 दिसंबर से दिन-रात्रि प्रारूप में एडीलेड में खेला जाएगा।

अनुभवी डेविड वॉर्नर चोट के कारण पहले टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे जबकि युवा पुकोवस्की भी भारत के खिलाफ अभ्यास मैच में 'कनकशन' का शिकार हो गए थे। हेलमेट से गेंद टकराने के बाद शुरुआती मैच में उनका खेलना संदिग्ध है। जो बर्न्स के लय में नहीं होने से ऑस्ट्रेलियाई टीम की परेशानी बढ़ गई है।

बार्डर ने कहा कि मार्नुस लाबुशेन और मार्क्स हैरिस इस भूमिका को निभा सकते है लेकिन शानदार लय में चल रहे 37 साल के शॉन मार्श भी बेहतर विकल्प है। बॉर्डर ने कहा, 'आप शीर्ष क्रम पर मार्नुस लाबुशेन को आजमा सकते है। उन्होंने दिखाया है कि वह नई गेंद का सामना कर सकते है।' उन्होंने कहा, 'शीर्ष क्रम में अनुभव की जरूरत को देखते हुए शॉन मार्श भी इस भूमिका को निभा सकते है।' मार्श ने अक्टूबर के बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हुए पिछली छह पारियों में तीन शतक के साथ एक अर्द्धशतक लगाया है।

उम्मीद है कि पहले टेस्ट तक फिट हो जाएंगे पुकोवस्की : कमिंस

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियाई उपकप्तान पैट कमिंस को उम्मीद है कि युवा सलामी बल्लेबाज विल पुकोवस्की भारत के खिलाफ 17 दिसंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से पूर्व समय पर ठीक हो जाएंगे। पुकोवस्की को भारत ए के खिलाफ अभ्यास मैच में सिर पर चोट लगी थी। वह दूसरे अभ्यास मैच में नहीं खेल सकेंगे। वह अपने कैरियर में नौवी बार कनकशन चोट का शिकार हुए हैं। कमिंस ने 'सिडनी मार्निंग हेराल्ड' से कहा, 'क्रिकेट में पिछले कुछ साल से यह काफी देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि उसे इसका अनुभव है और पता है कि कैसे वापसी करनी है। उसके पास विशेषज्ञों की सेवाएं हैं जो इसमें उसकी मदद करेंगे।' उन्होंने कहा, 'मैं उसके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उम्मीद है कि वह जल्दी ठीक होगा।' पुकोवस्की ने शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले सत्र में उनका खेलना तय था लेकिन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के कारण उन्होंने नाम वापिस ले लिया था।

ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, भारत के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हुए डेविड वॉर्नर

सिडनी।(एजेंसी)।

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ग्रोइन की चोट के कारणभारत के खिलाफ एडीलेड में 17 दिसंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। वॉर्नर ने कहा कि वह टेस्ट क्रिकेट में सौ फीसदी फिट होकर ही उतरना चाहते हैं और उनका लक्ष्य मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू हो रहा बॉक्सिंग डे टेस्ट है। उन्होंने कहा ,''अब चोट पहले से बेहतर है लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिये सौ प्रतिशत फिट होकर ही उतरना चाहता हूं ताकि विकेटों के बीच दौड़ और क्षेत्ररक्षण अपेक्षा के अनुरूप रहे।'' उन्होंने कहा ,''अभी मैं उस स्तर पर नहीं हूं। अगले दस दिन में काफी फर्क आ जायेगा।''

वॉर्नर को दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी थी और वह कैनबरा में तीसरा वनडे तथा तीन टी20 मैचों की श्रृंखला नहीं खेल सके थे। आस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने कहा ,'' उम्मीद है कि वह मेलबर्न टेस्ट से पहले फिट हो जायेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है।'' वॉर्नर के नहीं खेलने से पारी की शुरूआत को लेकर चयनकर्ताओं का सिरदर्द बढ जायेगा। विल पुकोवस्की को भारत ए के खिलाफ अभ्यास मैच में सिर में चोट लगी है। दूसरे सलामी बल्लेबाज जो बर्न्स खराब फार्म में हैं।

भारत ए के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच में हिस्सा लेंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम के ये खिलाड़ी

सिडनी। शानदार फार्म में चल रहे कैमरन ग्रीन और लेग स्पिनर मिशेल स्वेपसन को शुक्रवार से एससीजी पर शुरू हो रहे दिन रात के दूसरे अभ्यास मैच के लिये बुधवार को आस्ट्रेलिया ए टीम में चुना गया। पहले अभ्यास मैच में आस्ट्रेलिया ए के लिये नाबाद 125 रन बनाने वाले 21 वर्ष के ग्रीन इस प्रदर्शन को दोहराकर टेस्ट टीम में अपनी जगह पुख्ता करना चाहेंगे। दूसरी ओर भारत के खिलाफ तीनों टी20 खेलकर पांच विकेट लेने वाले स्वेपसन को आखिरी मैच में मैन आफ द मैच चुना गया था। पहला अभ्यास मैच ड्रा रहा था। **आस्ट्रेलिया ए टीम :** जो बर्न्स, मार्कस हैरिस, मोइजेस हेनरिक्स, कैमरन ग्रीन, निक मेडिंसन, एलेक्स कारे, बेन मैकडरमोट, सीन एबोट, विल सदरलैंड, हैरी कोंवे, मिशेल स्वेपसन, मार्क स्टीकेटी।

फिजियो से बात करने के बाद ही अभ्यास मैच में खेलने पर फैसला करूंगा : कोहली

सिडनी।(एजेंसी)

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मंगलवार को संकेत दिये कि वह आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पूर्व आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन दिन के अंदर शुरू होने वाले दूसरे अभ्यास मैच से बाहर रह सकते हैं। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सीमित ओवरों की श्रृंखला के बाद चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 17 से 21 दिसंबर के बीच एडीलेड में खेला जाएगा। कोहली इस मैच में टीम की अगुवाई करेंगे। इसके बाद वह अपने पहले बच्चे के जन्म के लिये स्वदेश लौट जाएंगे।

कोहली ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की 12 रन से हार के बाद कहा, ''मैं कल सुबह उठने के बाद देखूंगा कि मैं अभ्यास मैच में खेल सकता हूं या नहीं। इसमें खेलना या नहीं खेलना का फैसला करना मेरे हाथ में नहीं है और मैं पूरे मैच में खेलना पसंद करूंगा। मैं अपने फिजियो के पास जाऊंगा और उसी के बाद इस मैच में खेलने को लेकर फैसला करूंगा।'' आस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने कोहली की 85 रन की पारी के बावजूद भारत को क्लीन स्वीप करने से रोक दिया। भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीती। कुल मिलाकर कोहली खुश हैं कि उनकी टीम ने मुश्किल परिस्थितियों में जीत हासिल करने का तरीका पता कर लिया है।

उन्होंने कहा, ''हम वापसी करने और विरोधी टीम को दहशत में रखने के तरीके ढूंढ रहे हैं और श्रृंखला में जीत से हमने 2020 सत्र का शानदार अंत किया।'' पिछले मैच की तरह कोहली के साथ आखिरी क्षणों में हार्दिक पंड्या क्रीज पर थे और एक समय उन्होंने भारत की जीत की उम्मीद जगा दी थी। कोहली ने कहा, ''एक समय जब हार्दिक ने बड़े शॉट खेलने शुरू किये तो हमें लगा कि हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हमने बीच के ओवरों में धीमी बल्लेबाजी का खामियाजा भुगता। अगर उस समय 30 रन की भागदारी निभायी गयी होती तो हार्दिक के लिये काम आसान हो जाता। '' कोहली ने आस्ट्रेलिया के खेल प्रेमी दर्शकों का भी आभार व्यक्त किया जो कोविड-19 महामारी के खौफ के बावजूद बड़ी संख्या में स्टेडियम में पहुंचे। उन्होंने कहा, ''मैंने दर्शकों की उपस्थिति का भी अहसास किया। इससे आपको हमेशा प्रेरणा मिलती है। कुछ अवसरों पर हमारे समर्थकों ने हमें मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद की। आस्ट्रेलिया को भी बहुत अच्छा समर्थन मिला। हम खिलाड़ियों को दर्शकों की ऊर्जा का भी फायदा मिला। ''

टी20 श्रृंखला जीतने के बाद कोहली की नजर अब टेस्ट मैचों पर है और उन्होंने कहा कि वर्तमान टीम दो साल पहले यहां अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीतने वाली टीम से मजबूत है। उन्होंने कहा, ''हमें टेस्ट मैचों में भी यही प्रतिस्पर्धी रवैया अपनाना होगा। हमें यहां खेलने का अनुभव है और हम अच्छा स्कोर बना सकते हैं। हमें सत्र दर सत्र अच्छा स्कोर बनाने पर ध्यान देना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान टीम पिछली बार की टीम से अधिक मजबूत है। '' आस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच को खुशी है कि पहले दो मैचों में हार के बाद उनकी टीम अंतिम मैच जीतने में सफल रही। फिंच ने कहा, ''यह शानदार श्रृंखला थी और पहले दो मैचों में हम हार गये।

पहली बार हमने दो लेग स्पिनर (एडम जंपा और मिशेल स्वेपसन) को टीम में रखा और उन्होंने यहां की छोटी बाउंड्रीज के बावजूद साहसिक गेंदबाजी की। इसलिए श्रेय उन दोनों को जाता है।'' उन्होंने कहा, ''स्वेपसन ने शिखर (धवन) और विराट के सामने सातवां ओवर किया। जंपा ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हमने पिछले 18 महीनों में सीमित ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया और मुझे इस टीम पर गर्व है। '' स्वेपसन ने 23 रन देकर पांच विकेट लिये जिनमें धवन भी शामिल है। उन्हें मैन आफ द मैच चुना गया। उन्होंने कहा, ''इस पुरस्कार को पाकर और अपनी टीम को जीत दिलाकर खुश हूं।

डीआरएस पर बोले विराट कोहली, '15 सेकंड से पहले स्क्रीन पर रिप्ले दिखाना महंगा पड़ा'

सिडनी। (एजेंसी)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली इस बात से नाखुश है कि मैथ्यू वेड को डाली गई गेंद पर रिप्ले बड़ी स्क्रीन पर 15 सेकंड से पहले दिखाये जाने के कारण उनकी टीम डीआरएस नहीं ले सकी। भारत को तीसरे टी20 मैच में 12 रन से पराजय झेलनी पड़ी। वेड को टी नटराजन ने 50 के स्कोर पर पगबाधा आउट कर दिया था लेकिन उन्हें इस तरह जीवनदान मिला और उन्होंने 30 रन और बनाये। कोहली ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,'' हम 15 सेकंड की समयसीमा के भीतर बात ही कर रहे थे कि गेंद कहां पड़ी है कि स्क्रीन पर रिप्ले आ गया।'' उन्होंने कहा ,'' हमने रिव्यू लिया लेकिन अंपायर ने कहा कि स्क्रीन पर रिप्ले आ चुका है।''

रिव्यू लिया होता तो मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ता। कोहली ने कहा ,'' मैने अंपायर रॉड टकर से बात की। मैने पूछा कि इस हालत में क्या करना है तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, यह टीवी की गलती है।'' उन्होंने कहा कि भारतीय टीम प्रबंधन ने अधिकारियों को अपनी नाराजगी से अवगत कराया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय मैच में इस तरह की गलती अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा ,'' टीवी टीम की एक मामूली गलती इतनी भारी पड़ सकती है। उम्मीद है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा।

पूनिया, वलारिवन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मोना पार्थसारथी को सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार का पुरस्कार

नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुके पहलवान बजरंग पूनिया और युवा निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) 'इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020' में इस साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जबकि मोना पार्थसारथी को साल का सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार चुना गया।

इस पुरस्कार समारोह का आयोजन '10वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन: फिक्की टीयूआरएफ 2020' के मौके पर ऑनलाइन किया गया था। विजेताओं का चयन पिछले एक साल (2019-20) के प्रदर्शन और योगदान को ध्यान में रखकर किया गया। पिछले लगभग दो दशक से खेल पत्रकारिता से जुड़ी मोना पार्थसारथी को उनके सकारात्मक लेखन के लिए ज्यूरी ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिये चुना। खिलाड़ियों के खेल से जुड़ी रिपोर्टों और साक्षात्कार के अलावा उनके मानवीय पहलुओं को सामने लाने के कारण उन्होंने खेल पत्रकारिता में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

इस बीच टोक्यो ओलंपिक के लिए अमेरिका में अभ्यास कर रहे एशियाई खेलों (2018) के स्वर्ण पदक विजेता बजरंग ने पुरस्कार हासिल करने पर खुशी जताते हुए कहा, 'मुझे यह मान्यता देने के लिए मैं ज्यूरी और फिक्की का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। भविष्य में मेरा उद्देश्य फिर से अपना सर्वश्रेष्ठ देना और देश के लिए बहुत सारे पदक जीतना होगा। ऐसे पुरस्कार मुझे अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है।'

वलारिवन ने इस मौके पर आपने मेंटोर गगन नारंग और कोच नेहा चौहान का शुक्रिया अदा किया। इस 21 साल की महिला राइफल निशानेबाज ने कहा, 'मैं अपने परिवार के साथ हमेशा साथ देने के लिए अपने मेंटोर गगन नारंग और मेरी कोच नेहा चौहान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मुश्किल समय में मेरा समर्थन करने के लिए मैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) को इस मौके पर धन्यवाद देना चाहती हूं।'

फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवाड्र्स फिक्की द्वारा पूरे साल शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विभिन्न हितधारकों के योगदान को मान्यता देने का एक प्रयास है।इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी, भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आईआईएम) के निदेशक और इन पुरस्कारों के ज्यूरी सदस्य प्रो धीरज शर्मा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मुकुल मुद्गल और एमपीएल के ब्रांड (संचार) प्रमुख हिमांशु राज ने विजेताओं को ऑनलाइन पुरस्कार प्रदान किए।

पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, समाप्त किया 18 साल का क्रिकेट का सफर

क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की

नई दिल्ली।(एजेंसी)।

भारत के लिये 17 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पार्थिव पटेल ने बुधवार को खेल के तमाम प्रारूपों को अलविदा कह दिया। तीन महीने बाद अपना 36वां जन्मदिन मनाने जा रहे पार्थिव ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लिखा , 'मैं आज क्रिकेट के सभी प्रारूपों से विदा ले रहा हूं। भारी मन से अपने 18 साल के क्रिकेट के सफर का समापन कर रहा हूं।' सौरव गांगुली की कप्तानी में 17 वर्ष 153 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पार्थिव ने 65 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जिनमें 25 टेस्ट, 38 वनडे और दो टी20 मैच शामिल है। उन्होंने 1696 रन बनाये जिसमें टेस्ट क्रिकेट में 934 रन शामिल हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने चार अर्धशतक समेत 736 रन बनाये। इसके अलावा बतौर विकेटकीपर टेस्ट में 62 कैच लपके और 10 स्टम्पिंग की। उन्होंने 2002 में इंग्लैंड दौरे पर भेजा गया जब उन्होंने रणजी ट्राफी क्रिकेट में भी पदार्पण नहीं किया था। पार्थिव ने कहा ,'बीसीसीआई ने काफी भरोसा जताया कि 17 साल का एक लड़का भारत के लिये खेल सकता है। अपने कैरियर के शुरूआती वर्षों में मेरी इस तरह हौसलाअफजाई करने के लिये मैं बोर्ड का शुक्रगुजार हूं।' उन्होंने 2004 में भारतीय टीम से बाहर किये जाने के बाद पहला रणजी मैच खेला। पार्थिव ने 'दादा' यानी बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली समेत सारे कप्तानों को धन्यवाद दिया। महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद पार्थिव विकेटकीपर के तौर पर दूसरी पसंद हो गए और यदा कदा बतौर बल्लेबाज ही खेले। बाद में सीमित ओवरों में सलामी बल्लेबाज के रूप में कुछ मैच खेले। पार्थिव ने लेकिन हमेशा स्वीकार किया कि वह धोनी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें और दिनेश कार्तिक को धोनी से पहले टीम में अपनी जगह पक्की करने के मौके मिले थे। वह घरेलू क्रिकेट में काफी कामयाब रहे और 194 प्रथम श्रेणी मैचों में 27 शतक समेत 11240 रन बनाये। उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिये खेला। इस बार आरसीबी के लिये वह एक भी मैच नहीं खेल सके। उन्होंने कहा ,'मैं आईपीएल टीमों और उनके मालिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे टीम में शामिल किया और मेरा ध्यान रखा।' पार्थिव की कप्तानी में गुजरात ने 2016-17 में रणजी खिताब जीता। वह भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पहले कप्तान रहे जिनके साथ2 2013 में सैयद मुश्ताक अली ट्राफी खेला। पार्थिव ने कहा ,'मुझे सुकून है कि मैने गरिमा, खेल भावना और आपसी सामंजस्य के साथ खेला। मैने जितने सपने देखे थे, उससे ज्यादा पूरे हुए। मुझे उम्मीद है कि मुझे याद रखा जायेगा।

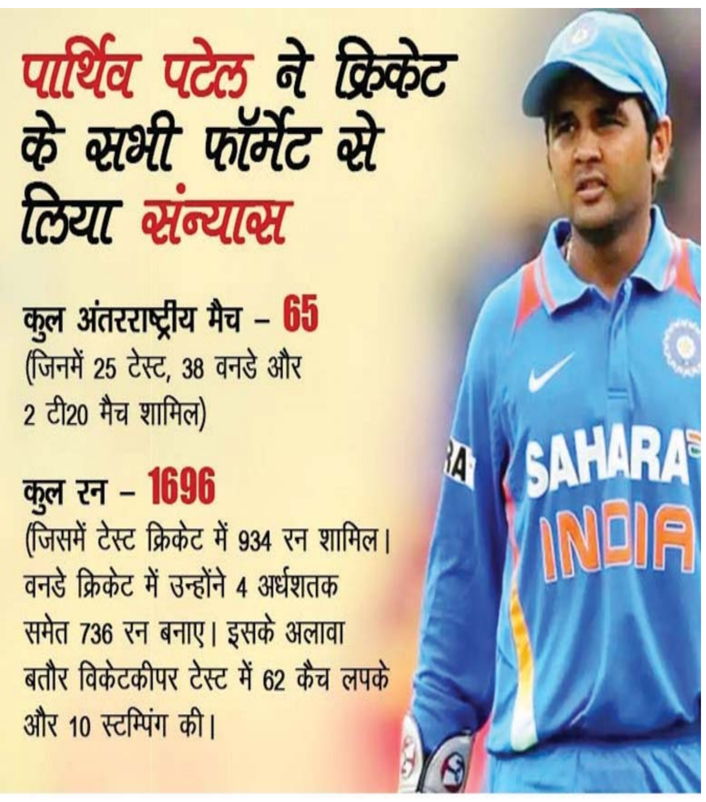

पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास

कुल अंतरराष्ट्रीय मैच – 65
(जिनमें 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 टी20 मैच शामिल)

कुल रन – 1696
(जिसमें टेस्ट क्रिकेट में 934 रन शामिल। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 4 अर्धशतक समेत 736 रन बनाए। इसके अलावा बतौर विकेटकीपर टेस्ट में 62 कैच लपके और 10 स्टम्पिंग की।

पेंच पार्क में दिखते हैं कुदरत के अनोखे रंग

महाराष्ट्र के नागपुर और मध्य प्रदेश के सिवनी के बीच 'पेंच नेशनल पार्क' ऐसी जगह है जहां रुखे व्यवहार वाला आदमी भी कुछ दिन रुक जाए तो वह भी काव्यात्मक लहजे में बातें करने लगेगा। पेंच की खूबसूरती को समझने के लिए 292 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस घने जंगल में आपको घूमना पड़ेगा।

जिन जगहों पर कुदरत दिल से मेहरबान रही है उनमें से पेंच भी एक है। पेंच आने वाले पर्यटकों का पहला सामना अपनी उछलकूद में मग्न बंदरों से होता है। कच्ची मगर सलीकेदार सड़क के चारों ओर घने झुरमुटों में से स्वछंद विचरते हिरण, सांभर और चीतल जरूर ठुमक कर पर्यटकों का स्वागत करते हैं मगर अपनी उत्सुक निगाहों को आप से हटा कर कुलाचें भरने का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। हर दूसरे मोड़ पर ये दोबारा आपके सामने नजर आ जाते हैं।

पेंच में शेर का दिखना मौके की बात है। यहां विचरते समय बीच-बीच में आपको नीलगाय, जंगली भैंसा, जंगली सूअर और जंगली कुत्ता आदि के साथ ही अन्य जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे।

पेंच में कुछ घंटे गुजरने के साथ ही आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि स्वच्छ हवा या आक्सीजन क्या होती है। सुबह-शाम पक्षियों की संगीतमय चहचहाहट के जादू से बच पाना भी किसी के बूते की बात नहीं है और न ही रंगबिरंगे पक्षी संसार को इतने नजदीक से देखने का अवसर चूकने की।

पेंच नेशनल पार्क में अब रुकना भी सरल हो गया है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों के प्रति अपनी गंभीरता को समझते हुए किपलिंग कोर्ट का निर्माण करवाया है। 20 कमरों का तमाम आधुनिक सुख-सुविधाएं लिए किपलिंग कोर्ट मोगली के जंगल में आप का घर ही है। किपलिंग कोर्ट के कमरे आम होटलों जैसे एक-दूसरे से सटे नहीं हैं और न ही आमने-सामने हैं। यह एक छोटी बस्ती की तरह चारों तरफ दोमंजिला शक्ल में फैले हुए हैं।

नागपुर और सिवनी के बीच खवासा गांव उतर कर मात्र 10 किलोमीटर अंदर जाकर जब पेंच का जीवन तबियत से जीने की इच्छा हो तो जरूरी है कि आप चश्मा ले जाएं, दूरबीन भी और कैमरा भी। जीप से घूमते समय पानी की बोतल साथ रखें। खाने-पीने के लिए गेट पर काफी रेस्तरां हैं साथ ही वन विभाग की कैंटीन और रेस्ट हाउस भी यहां उपलब्ध हैं।

मौसम कोई भी हो, पेंच में सुबह-सुबह सर्दी का एहसास जरूर होता है। सर्दियों में शाम भले ही किपलिंग कोर्ट के अंदर कमरे में कुछ सोचते, गुनगुनाते, थिरकते या नीचे मैदान में बैठ साथी पर्यटकों से बातचीत करते गुजारी जाए लेकिन गर्मियों की शाम में अगर बगैर दीवारों वाले तितली रेस्तरां में कुछ ठंडा-गरम पिया जाए तो पेंच आने की कीमत वसूल हो जाती है।

वनों का सुंदर उपहार कोडैकनाल

कोडैकनाल भारत का एक आकर्षक पहाड़ी पर्यटन स्थल है जो तमिलनाडु राज्य में बसा डिंडागुल जिले का एक शहर है। यह समुद्र तल से 2133 मीटर की ऊंचाई पर एक पठार के ऊपर है। तमिल में कोडैकनाल का अर्थ वन का उपहार है। कोडै शब्द के चार अलग-अलग अर्थ होते हैं- पहला 'जंगल का अंतिम छोर', दूसरा 'लताओं का जंगल', तीसरा 'गर्मियों का जंगल' और चौथा 'जंगल का उपहार'। यहां की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे 'हिल स्टेशनों की राजकुमारी' भी कहते हैं

कोडैकनाल हिल रिजॉर्ट अपनी सुंदरता और शांत वातावरण से सबको सम्मोहित कर लेता है। यहां घूमने का मजा कुरिंजी नामक फूल के खिलने के समय दोगुना हो जाता है। हालांकि यह फूल बारह साल में एक बार खिलता है। यहां के लोग कुरिंजी के फूल को देखना अपनी शान समझते हैं। जब यह खिलता है तो पहाड़ियों की सुंदरता देखते बनती है। इसकी खुशबू मदहोश कर देने वाली होती है। विशाल चट्टान, शांत झील, फलों के बागीचे और पाइन के जंगलों से आती शुद्ध हवा यहां के वातावरण को सुगंधित और गुलजार बना देती है। कोडैकनाल का उल्लेख ईसा पूर्व के संगम साहित्य में मिलता है। पलानी हिल्स के आसपास के क्षेत्र में उस समय पेलियंस और पुलयंस नामक आदिम जनजाति निवास करती थी। 1845 में अंग्रेजों ने यहां हिल स्टेशन स्थापित किया था। ब्रिटिश प्रशासकों और मिशनरियों का यह पसं दीदा हिल स्टेशन था। कोडैकनाल की स्थापना 1863 में हुई थी। इस सूबसूरत शहर के दर्शनीय स्थल-

कोडैकनाल झील

इस खूबसूरत सितारानुमा झील का निर्माण एक अंग्रेज ने किया था। जो 60 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इसके चारों ओर की हरियाली पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस झील का बोट क्लब रोमांचक रेसिंग ट्रिप की सुविधा उपलब्ध कराता है।

कोकर्स वाक

लेफ्टिनेंट कोकर के नाम से इस स्थान का नाम कोकर्स वाक पड़ा। कोकर ने कोडैकनाल का मानचित्र तैयार किया था। यह शहर से एक किलोमीटर दूर मनमोहक पर्यटन स्थल है। यहां से आसपास की पहाड़ियों तथा मदुरै शहर का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैदानों से खूबसूरत दिलकश नजारों का लुत्फ लिया जा सकता है। यहां की प्रसिद्ध पिलर रॉक्स चट्टानें कोडैकनाल से 7.4 किलोमीटर दूर हैं। ये 122 मीटर ऊंची है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। यह स्थान पिकनिक के लिए भी उपयुक्त है।

ब्रायंट पार्क

बेरियम झील के पूर्व दिशा में फैला ब्रांयट पार्क स्थित है। यह पार्क फूलों तथा संकर प्रजाति के विभिन्न पेड़-पौधों के लिए जाना जाता है। यहां एक ग्लास हाउस में विभिन्न किस्म के फूल खिले रहते हैं। मई महीने में यहां उद्यान मेला लगता है।

बेरियम झील

यह खूबसूरत झील पिकनिक के लिए लोकप्रिय स्थल है। प्राकृतिक सुंदरता से भरी यह झील कोडै कनाल बस स्टे शन से 21 किलोमीटर दूर है। इस झील से पेरियाकुलम नगर को पानी की सप्लाई होती है। झील की खोज और सुधार कार्य ब्रिटिश आर्मी कर्नल हेमिल्टन द्वारा 1864 में किया गया था।

शेनबागानूर संग्रहालय

झील से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह संग्रहालय स्थित है। इसकी देखरेख सेक्रेड हार्ट कॉलेज द्वारा की जाती है। यहां का आर्किडोरियम भारत के सबसे बेहतर आर्किडोरियम में से एक माना जाता है।

कुरिंजी अंदावर मंदिर

यह मंदिर कोडैकनाल से 3.2 किलोमीटर दूर है। यहां पर 'लार्ड मुरुगन' की एक आकर्षक प्रतिमा रखी हुई है। यहां से पलानी पहाड़ियों तथा वैगाई डैम का खूबसूरत दृश्य मन को मोह लेता है।

बीयरशोला फाल

यह खूबसूरत पिकनिक स्थल कोडैकनाल से 16 किलोमीटर दूर है। यहां अक्सर भालुओं को पानी पीते देख जा सकता है। भालुओं की उपस्थिति के कारण इस झरने का नाम बीयरशोला पड़ा।

सिल्वर कासकेड प्रपात

यह आकर्षक जलप्रपात कोडैकनाल झील से 8 किलोमीटर दूर है। झील का अतिरिक्त जल 180 फीट की ऊंचाई से झरने के रूप में गिरता है। यहां के शांत और सौम्य वातावरण का पर्यटक भरपूर आनंद लेते हैं।

बोट क्लब

यह बोट क्लब 1910 में स्थापित किया गया था। 1932 से पहले यह आम लोगों और पर्यटकों के लिए नहीं था। मात्र कुछ चुनिंदा सदस्य ही बोटिंग का आनंद ले सकते थे। बाद में पर्यटकों और आम लोगों को भी सुविधा दे दी गई।

वेधशाला

कोडैकनाल से 3.2 किलोमीटर दूर स्थित इस वेधशाला का निर्माण 1899 में किया गया था। 2347 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह वेधशाला कोडैकनाल की सबसे ऊंची जगह है। यहां से प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखता है।

टेलीस्कोप हाउस

घाटी और उसके आसपास की सुंदरता को देखने के लिए दो टे लीस्कोप हाउस स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा सौर भौतिक वेधशाला, ग्रीन वैली व्यू, गुना गुफाएं, डॉल्फिन नोज, थालाइयर झरना आदि जगहों की सैर कर सकते हैं। फलों में नाशपाती के लिए यह जगह प्रसिद्ध है। चॉकलेट प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग माना जाता है। साहसिक गतिविधियों में ट्रैकिंग, बोटिंग, हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग का आनंद लिया जा सकता है।

कब और कैसे जाएं

सालभर मौसम अच्छा रहता है। वैसे, अच्छा समय अप्रैल से अगस्त उत्तम है। सर्दियों के दौरान इस जगह की यात्रा अच्छी रहती है। निकटतम हवाई अड्डा मदुरै है, जो यहां से 120 किलोमीटर दूर है। यहां से बस या टैक्सी द्वारा कोडैकनाल पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कोडै रोड है, जो कोडैकनाल से 80 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग के लिए दक्षिण भारत के कई मुख्य शहरों से सीधी बस सेवा द्वारा जुड़ा है।

सागर किनारे लक्षद्वीप

अरब सागर की गोद में बैठे छोटे ये द्वीप अपनी सुंदरता में अद्वितीय और आकर्षक हैं। ये भारत के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। मुख्य भूमि से दूर इनका प्राकृतिक सौंदर्य, प्रदूषणमुक्त वातावरण, चारों ओर समुद्र और इसका पारदर्शी तल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।

समुद्री जल में तैरती असंख्य प्रजातियों की रंगबिरंगी मछलियाँ इन द्वीपों की सुंदरता को चार चाँद लगा देती हैं। हर द्वीप पर नारियल व पाम के झूमते हरे-भरे वृक्ष हैं। और साथ है कोरा-कुँवारा समुद्र जिसका नीला पानी आपको अनोखी पवित्रता का अहसास कराता है।

लक्षद्वीप भारत के एकमात्र मूँगा द्वीप हैं। इन द्वीपों की श्रृंखला मूँगा एटोल हैं। एटोल मूँगे के द्वारा बनाया गई ऐसी रचना है जो समुद्र की सतह पर पानी और हवा मिलने पर बनती है। सिर्फ इन्हीं परिस्थितियों में मूँगा जीवित रह सकता है। यहाँ के निवासी केरल के निवासियों से बहुत मिलते-जुलते हैं। यह द्वीप पर्यटकों का स्वर्ग है। यहाँ का नैसर्गिक वातावरण देश-विदेश के सैलानियों को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। अब केंद्र सरकार इन द्वीपों का पर्यटन की दृष्टि से तेजी से विकास कर रही है।

समुद्र जल में जो जीव सृष्टि है, वह धरातल के ऊपर के प्राणियों से कम सुंदर और आकर्षक नहीं है। ये द्वीप प्रकृति की एक अद्भुत देन हैं। यह आश्चर्य की बात है कि यहाँ की धरती का निर्माण मूँगों द्वारा किया गया। उन्होंने ही मानव के रहन-सहन के उपयुक्त बनाया। यह द्वीप पर्यटकों का स्वर्ग है। यहाँ का नैसर्गिक वातावरण देश-विदेश के सैलानियों को बरबस अपनी ओर खींच लेता है।

द्वीप

अगत्ती लक्षद्वीप का बेहद खूबसूरत लैगून में से है। यहाँ एयरपोर्ट भी है। लक्षद्वीप में यहीं से प्रवेश किया जाता है। यहीं पर 20 बिस्तरों वाला एक पर्यटक काम्पलैक्स भी है।

बंगारम

आँसू के आकार के इस द्वीप में चारों ओर क्रीमी रंग की रेत बिखरी हुई है। लक्षद्वीप के हर द्वीप की तरह यहाँ भी नारियल के वृक्ष सघन मात्रा में हैं जो दिन की तीखी गर्मी में भी ठंडक देते हैं।

कवरत्ती

कवरत्ती यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। यह सबसे अधिक विकसित भी है साथ ही यहाँ द्वीपवासियों के अलावा अन्य लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। पूरे द्वीप में 52 मस्जिद हैं, सबसे खूबसूरत मस्जिद है उज्र मस्जिद। कहा जाता है कि यहाँ के पानी में चमत्कारी शक्ति है।

इस द्वीप में एक्केरियम भी है जिसमें सुंदर मछलियों की प्रजातियाँ हैं। यहाँ काँच की तली वाली नौका में बैठकर आप समुद्री दुनिया का नजारा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वाटर स्पोर्ट्स जैसे केयाकिंग, कनोइंग और स्नोरकेलिंग का मजा भी ले सकते हैं।

कालपेनी

यहाँ तीन द्वीप हैं जिनमें आबादी नहीं है। इनके चारों ओर लैगून की सुंदरता देखने लायक है। कूमेल एक खाड़ी है जहाँ पर्यटन की पूरी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ से पित्ती और थिलक्कम नाम के दो द्वीपों को देखा जा सकता है। यहाँ आप तैर सकते हैं, रीफ पर चल सकते हैं, नौका में बैठकर घूम सकते हैं और कई वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं।

कदमठ

एक जैसी गहराई और दूर अनंत तक जाते किनारे कदमठ को स्वर्ग बनाते हैं। यही एकमात्र द्वीप है जिसके पूर्वी और पश्चिमी दोनों ओर लैगून हैं। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की बेहतरीन सुविधाएँ हैं।

मिनिकॉय

यह कवरत्ती से 200 किमी दूर दक्षिण में है। मालदीव के करीब होने के कारण यहाँ भिन्न संस्कृति के दर्शन होते हैं। मिनिकॉय नृत्य परंपरा के मामले में बेहद समृद्ध है। विशेष अवसर पर यहाँ लावा नृत्य किया जाता है। यहाँ खासकर तूना मछली का शिकार और नौका की सैर आनंददायी है। अँग्रेजों के द्वारा 1885 में बनवाया गया प्रकाश स्तंभ देखने लायक है, पर्यटक यहाँ ऊपर तक जा सकते हैं।

कैसे जाएँ

हवाई मार्ग से कोचीन से अगत्ती द्वीप तक सीधी हवाई सेवा है। अगत्ती से हेलिकॉप्टर या बोट के माध्यम से आगे जाया जा सकता है। दूसरे द्वीपों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। पानी के जहाज से केरल के कोचीन से जहाज की सेवा भी उपलब्ध है।

कब जाएँ

अक्टूबर-नवंबर में यहाँ बारिश होती है और पानी के जहाज चलना बंद हो जाते हैं। फिर भी हेलिकॉप्टर के माध्यम से आप यहाँ जा सकते हैं। इन दिनों मौसम कुछ ठंडा हो जाता है लेकिन अन्य दिनों में गर्मी रहती है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला का विरोध, कैथल में धरना छोड़कर लौटना पड़ा

कैथल। भारत बंद के दौरान तितरम मोड़ पर जाम लगाए किसानों के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला पहुंचे और समर्थन का ऐलान किया। वे खुद भी धरना दे रहे किसानों के बीच बैठ गए। इसी बीच किसानों ने राजनीतिक दलों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। विशेष तौर पर युवाओं ने रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी सवाल-जवाब किए। देखते-देखते हंगामा शुरू हो गया और किसानों ने रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ नारेबाजी शुरु कर दी। कुछ देर तक सुरजेवाला किसानों के बीच जमीन पर ही बैठे रहे, लेकिन जब वे उठे तो हालात बेकाबू हो गए। किसानों ने उन्हें घेर लिया और इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की शुरू हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने सुरजेवाला के घेर लिया और वहां से कुछ ही दूरी पर खड़ी उनकी कार तक लेकर पहुंचे। इस दौरान भी किसान उनके पीछे-पीछे नारेबाजी करते चल रहे थे।

प्रदर्शनकारी किसानों के भारी विरोध के चलते असहज स्थिति में सुरजेवाला को तितरम मोड़ से धरना छोड़कर लौटना पड़ा। दरअसल, एक नेता ने सुरजेवाला के पहुंचते ही उनकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। किसानों ने उसे मना भी किया, लेकिन वह जारी रहे। किसानों ने कहा कि यह मंच नेताओं और राजनीतिक पार्टियों का नहीं, लेकिन वह माइक थामे नेता नहीं रूके। इस पर किसान बिफर गए और विरोध शुरु कर दिया। इससे पहले सुरजेवाला ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली का दरबार सिर्फ अंबानी-अड़ानी की रक्षा करने के लिए है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हरियाणा-पंजाब का किसान उग्रवादी है। किसान के खेत का पानी अब उसकी आंख का पानी बन गया है। दिल्ली की सल्तनत की रोटी किसान की वजह से चलती है। दिल्ली और चंडीगढ़ के दरबार अगर किसान को इस तरह से प्रताड़ित करेंगे तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी। यह दलों की राजनीतिक लड़ाई नहीं है। यह रोजी-रोटी की लड़ाई है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, हम सभी राजनीति दल किसान के साथ खड़े होंगे। कांग्रेस प्रायोजित किसान आंदोलन के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि किसान न तो बीजेपी का है और न कांग्रेस का है। सुरजेवाला ने कहा किसान को सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दीजिये, हम खुद मोदी जी की तारीफ करेंगे। कानून में लिखिए कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। हम सब उनकी जय-जयकार करेंगे, लेकिन लाठियां मारेंगे, आंसू चलाएंगे और रोड़े अटकाएं तो अगर किसान ने रोटी बंद कर दी तो दिल्ली का दरबार एक दिन नहीं चल पाएगा।

सिरसा में बारिश के पानी से भूमिगत जल सुधारने के लिए अनोखा प्रयास शुरू, 70 लाख होंगे खर्च

सिरसा। जब भी बारिश होती है, बारिश का पानी व्यर्थ ही बहता रहता है। दूसरी तरफ भूमिगत जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। जिला प्रशासन ने गिरते भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए कवायद शुरू कर दी। जिसके तहत बड़े सरकारी भवनों की छतों को बोरवेल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। जिसके लिए लघु सचिवालय की भवनों की छतों को बोरवेल सिस्टम से जोड़ने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। जिले में 31 बड़े सरकारी भवनों की छतों को बोरवेल सिस्टम से जोड़ने के लिए करीब 70 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

करीब 320 फुट तक होगा बोर

बारिश के पानी को बोरवेल सिस्टम में डाला जाएगा। इसके तहत 31 जगह पर 320 फुट तक बोरवेल किया जाएगा। इसके बाद सरकारी भवनों की छतों को बोर सिस्टम से जोड़ा हुआ है। इससे जब भी बारिश होती है। बारिश का पानी बोरवेल में डालकर रिचार्ज होता रहेगा। लघु सचिवालय परिसर में चार जगह पर बोरवेल से सरकारी भवनों की छतों को बोरवेल से जोड़ने के लिए कार्य शुरू कर दिया है।

विवि के भवनों की छत को जोड़ा हुआ बोर सिस्टम से

विश्वविद्यालय में बने भवनों के पास बोर सिस्टम किया हुआ है। जिसके तहत 350 फीट तक बोर किए हुए हैं। भवनों की छतों को बोर सिस्टम से जोड़ा हुआ है। इससे जब भी बारिश होती है। बारिश का पानी बोरवेल में डालकर रिचार्ज किया जाता है। विश्वविद्यालय के टैगोर भवन, पुस्तकालय, सीवी रमन भवन, आंबेडकर लॉ भवन, छात्रावास व सूचना केंद्र की छतों को बोरवेल सिस्टम से जोड़ा हुआ है। इसी के साथ विश्वविद्यालय के अंदर आवासीय कालोनी व छात्रावास के व्यर्थ पानी को स्प्रिंग सिस्टम से पेड़ पौधों को दिया जाता है। इससे जगह जगह विश्वविद्यालय में पार्क तैयार किए हैं। जो विश्वविद्यालय के सौंदर्य को बढ़ावा दे रहे हैं।

शहर में भूमिगत पानी की स्थिति

वर्ष	कितने मीटर पहुंचा जलस्तर
2004	18.18 मीटर
2005	19.91 मीटर
2006	23 मीटर
2007	25.38 मीटर
2008	26.63 मीटर
2009	29.54 मीटर
2010	29.56 मीटर
2011	36.6 मीटर
2012	37.96 मीटर
2013	37.11 मीटर
2014	38.07 मीटर
2015	37.53 मीटर
2016	44.31 मीटर
2017	44.41 मीटर
2018	46.18 मीटर
2019	46.31 मीटर
2020	48.00 मीटर

जिले में 31 जगह पर बोरवेल सिस्टम से सरकारी भवनों की छतों को जोड़ा जाएगा। जिसके लिए 70 लाख रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। लघु सचिवालय परिसर में चार जगह पर बोर किए जाएंगे। इससे जैसे ही बारिश होगी। बारिश का पानी बोरवेल सिस्टम में चला जाएगा। इससे भूमिगत जल सुधारने में मदद मिलेगी।

रामनिवास, जेई, बीएंडआर विभाग, सिरसा

दोहरे चेहरे का असली रंग दिखा गई राजनीति

फतेहाबाद। भारत बंद के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों का खुलकर समर्थन रहा। लेकिन किसानों के तथाकथित रहनुमाई करने वाले राजनीतिक दल दोहरे चरित्र का अपना असली चेहरा दिखा गए। किसानों और किसानी के नाम राजनीति करने वाले विपक्ष कतई हमदर्द बनकर सामने आए। गुटों में बंटी कांग्रेस ने महज औपचारिकताएं पूरी की तो किसान नेता चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति करने वाला इनेलो पूरे भारत बंद के दौरान नदारद।

टोहाना में भी अलग से नहीं दिखाई दे सके। आम आदमी पार्टी के नेता विज्ञप्तियों में बोले। सुबह से ही विपक्षी एकता की झलक भारत बंद के दौरान देखने की अपेक्षा थी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखा। हां, कांग्रेस की खेमाबंदी जरूर इस बंद के दौरान भी दिखाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा अपने पुत्र आनंदवीर के साथ बाजार में घूमते व अपील करते नजर आए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के खेमे से विनीत पूनिया किसान संगठन के प्रदर्शन में शामिल हुए।

पूर्व सीएम हुड्डा बोले-किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी और मंडियों का विस्तार जरूरी

चंडीगढ़। हरियाणा के विपक्षी राजनीतिक दलों ने तीन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसानों के हक में आवाज उठाई है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में प्रेस कान्फ्रेंस कर कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का संरक्षण जरूरी है। यह तभी हो पाएगा जब सरकारी मंडियों का विस्तार होगा। हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने सरकारी मंडियों के विस्तार को प्राथमिकता दी थी। मौजूदा सरकार प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा दे रही है। इससे सरकारी मंडियां कमजोर होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव के बाद पूंजीपति किसान के उत्पाद की बेहिसाब जमाखोरी करेगा और उससे सस्ता खरीदकर बाजार में महंगे रेट पर बेचेगा। किसान की खुशहाली में हर वर्ग की उन्नति छिपी है। कृषि कानूनों के खिलाफ इस आंदोलन में किसान अकेला नहीं है। कांग्रेस और हर वर्ग का उन्हें पूरा साथ मिल रहा है। भारत बंद के सफल और शांतिपूर्ण होने का दावा करते हुए हुड्डा ने कहा कि कृषि प्रधान देश में किसानों की अनदेखी उचित नहीं है। तीन कृषि कानूनों के जरिये किसानों से फसल की एमएसपी और मंडियां छीनने की साजिश रची जा रही है। हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार अमेरिका की नीति भारत में लागू करना चाहती है। सरकार को समझना चाहिए कि अमेरिका और भारत दोनों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। अमेरिकी कृषि व्यवस्था का स्पष्ट नियम है कि या तो आप बड़े किसान बन जाओ या आप खेती छोड़ दो, इसीलिए अमेरिका में ज्यादातर सिर्फ वे किसान बचे हैं, जिन्हें वहां की सरकार भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा सब्सिडी देती है, लेकिन भारत में छोटी जोत वाले किसानों की तादाद अधिक है, जिनसे लगातार सब्सिडी का लाभ छीना जा रहा है। उन्होंने कृषि मंत्री जेपी दलाल के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की बात कही है।

किसानों के साथ खड़े नजर आए कांग्रेस कार्यकर्ता – सैलजा

हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कु. सैलजा ने शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए किसानों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों के साथ हर वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन में भागीदारी की। अब केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़कर तीनों कृषि कानून वापस ले लेने चाहिये। सैलजा ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों की आवाज बनकर आंदोलन में खड़े हुए हैं। इसके लिए वह उनकी आभारी हैं।

शहीद किसानों को एक-एक करोड़ दे सरकार – अभय

हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके इनेलो महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। अभय चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान अन्नदाता द्वारा दी गई शहादत बेकार नहीं जाएगी।

किसानों की मौत की जिम्मेदार सरकार है। अभी भी समय है कि केंद्र सरकार गंभीरता दिखाते हुए तुरंत कृषि कानूनों में बदलाव कर फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी और एमएसपी पर फसल न खरीदने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान करने की मांग पूरी करे।

शहीद किसानों के परिजनों को दो-दो लाख देंगे कुंडू

महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हरियाणा के किसानों के परिवारों को अपने निजी कोष से दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार से मांग की है कि किसान आंदोलन में शहीद होने वाले सभी किसानों के आश्रित परिवारों को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बलराज कुंडू ने सरकार से कहा कि किसानों की चिकित्सा सुविधा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए जाएं।

कैदी के पास से मिला मोबाइल, कैदियों ने चंदा लगाकर 85 हजार में खरीदा था, सात करते थे बात

गुरुग्राम। भोंडसी जेल में बंद कैदियों के पास से मोबाइल मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जेल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा तलाशी के दौरान एक कैदी (विचाराधीन बंदी) के पास से सैमसंग कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ है। आरोपित ने जेल में ही बंद एक कैदी से 26 हजार की कीमत वाला मोबाइल 85 हजार में खरीदा था। मोबाइल से कॉल सात अन्य कैदी भी करते थे। भोंडसी थाना पुलिस ने जेल अधीक्षक की ओर से मिली शिकायत के बाद मामला दर्ज कर ली। पुलिस कॉल डिटेल निकाल कर यह पता लगाएगी की आरोपित किस-किस से बात करते थे। उनका संपर्क किसी बदमाश से तो नहीं था। क्योंकि पहले कई मामले सामने आ चुके हैं किजेल में बंद कैदी गैंगस्टरों से संपर्क में रहते हैं। सोमवार शाम करीब सात बजे जेल के सुरक्षा कर्मी कैदियों की तलाशी ले रहे थे तभी विचाराधीन बंदी राहुल की लोवर की जेब से मोबाइल मिला। पूछताछ में राहुल ने कबूला कि उसने मोबाइल दूसरे कैदी साहुन से खरीदा था। रकम राहुल के अलावा जेल में बंद सदरूदीन,इमरान, इस्ताक,इमरान पुत्र हुसैन, शाहीद, मोहम्द नदीम, मोहम्मद ईशा ने मिलकर 85 हजार की रकम दी थी। सभी बारी-बारी से मोबाइल से कॉल भी करते थे। अधिकतर समय मोबाइल राहुल के पास ही रहता थो। मोबाइल चार्ज कैसे किया जाता था पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है। शक है कि जेल का कोई कर्मचारी मोबाइल चार्ज कर राहुल को देता था उसके बदले वह रकम लेता था। पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने बताया राहुल से पुलिस पूछताछ कर यह भी पता लगाएगी। राहुल वाहन लूट व अन्य आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि, इस माह तीसरी बार कैदी के पास से मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल मिलने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

गांव का पानी कितना शुद्ध है, इसकी जांच अब उपभोक्ता खुद कर सकेंगे

फतेहाबाद। पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पुणे से फील्ड टेस्टिग किट मंगवाई है। इसमें पानी डालकर रखने के 12 से 24 घंटे में पानी की गुणवत्ता का प्रमाण मिल जाएगा। किट में डालने के बाद पानी काला हो गया तो वह पीने योग्य नहीं है। ऐसे गांव में पानी की शुद्धता को लेकर विभाग की ओर से समाधान के प्रयास किए जाएंगे। मंगाई गई 2000 कीटों को सभी गांव में बांटा जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला संरक्षण अधिकारी शर्माचंद लाली ने बताया कि कीट बांटने के लिए लिए ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी लगाई गई है। जिले में 257 ग्राम पंचायतें हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को पानी की शुद्धता जांच करने के लिए कीट दी जाएगी ताकि ग्रामवासी अपने यहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दी जा रही पानी की सप्लाई की जांच कर सकें। प्रत्येक गांव में 5 से 7 कीट दी जाएगी। जो अलग अलग गांव में सैंपलिग की जाएगी। पेयजल संकट के लिए इन नंबरों पर करें फोन – कहीं भी लीकेज दिखती है तो विभाग के टोल फ्री नंबर 1800180 5678 पर शिकायत दर्ज कराएं। किट द्वारा की गई जांच में पानी का सैंपल फेल हो जाता है तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की लैब में पानी दोबारा चेक किया जाएगा। यहां भी पानी का सैंपल फेल हो जाता है तो विभाग पानी दूषित होने का कारण जानकर उसका समाधान करेगा। अगर ट्यूबवैल में कमी मिलती है तो उसकी जगह दूसरा ट्यूबवैल भी लगाया जाएगा।

भारत बंद : हरियाणा में बंद में किसानों के बजाए विपक्षी दलों के नेता ही दिखे सक्रिय

नई दिल्ली। तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसाना संगठनों के आह्वान पर भारत बंद के दौरान हरियाणा में किसानों से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता ही सक्रिय रहे। इनमें कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। कई कांग्रेस नेता किसानों के धरने में पहुंचे, लेकिन कई जगह उनको किसानों से ठीक से रिस्पांस नहीं मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला को किसानों ने बोलने तक नहीं दिया।

सामान्य रूप से खुले दिल्ली से लगते हरियाणा के जिलों में बाजार

दोपहर तक लोग एहतियात के तौर पर राजमार्गों पर नहीं निकले। इससे राजमार्ग इस दौरान जरूर कुछ देर तक सूने नजर आए। बंद सफल बनाने के लिए किसानों की बजाये रविवार शाम से ही गैर भाजपाई दलों के नेता और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि सक्रिय हो गए थे मगर प्रशासनिक सूझबूझ के चलते मंगलवार सुबह से ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कर्मचारी संघों के नेताओं को उनके घरों पर ही नजरबंद रखा गया।

लाकडाउन के बाद बंद से तौबा

कोरोना संक्रमण से बचाव को लागू रहे लंबे लाकडाउन के बाद उद्योग और व्यापारी संगठनों ने भारत बंद से तौबा कर ली थी। कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े व्यापारी संगठनों ने बंद का साथ देने का आह्वान किया तो आम व्यापारियों और दुकानदारों ने इसका खुलकर विरोध किया।

भारत बंद के आह्वान के पीछे बेशक किसान का आंदोलन था मगर व्यापारियों ने बेझिझक बंद में हिस्सा नहीं लिया। व्यापारियों के लिए यह बात भी सुकून भरी रही कि प्रमुख बाजारों में कोई जबरदस्ती बंद के लिए नहीं आया। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वरिष्ठ उप प्रधान शम्मी कपूर का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जब कोरोना जैसी महामारी से बचाव को लाकडाउन के बारे में नहीं सोचा जा रहा है तो विपक्षी दलों को भारत बंद का आह्वान नैतिकता के आधार पर नहीं करना चाहिए था। बेशक उद्योग-व्यापार जगत ने भारत बंद में हिस्सा नहीं लिया है मगर फिर भी एहतिहात के तौर पर अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष काफी नुकसान हुआ है।

भारत बंद पूरी तरह से सफल : पूनिया

फतेहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया सचिव डॉ. विनीत पुनिया ने हज़ारों किसान आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के सफल बन्द ने साफ कर दिया है कि केंद्र के 3 काले कृषि कानूनों का केवल किसान ही नही, बल्कि देश का हर नागरिक विरोध कर रहा है। देश की जनता भी नहीं चाहती कि देश के किसानों के साथ ऐसा अन्याय ना हो।

डॉ पुनिया ने कहा की देश के किसान, व्यापारी, मजदूर, आम जनता बधाई की पात्र है। इस सफल बन्द के बाद भाजपा की जन विरोधी सरकार का पतन साफ दिखाई देने लगा है। पूर्व सीपीएस व वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की।

सहकारी बैंक गबन मामले में चार नामजद

टोहाना। शहर पुलिस ने दी फतेहाबाद सेंट्रल को को-आप्रेटिव बैंक हिम्मतपुरा टोहाना शाखा के प्रबंधक की शिकायत पर चार लोगों के विरुद्ध लाखों रुपये का गबन मामले में 4 लोगों के विरुद्ध धारा 409 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में शाखा प्रबंधक वेद प्रकाश ने बताया कि मॉडल टाऊन स्थित हिम्मतपुरा शाखा में उसने 27 अगस्त 2020 को ज्वाइन करने के बाद वहां की तिजोरी की चाबी गुम होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। वहीं जब 28 अगस्त को उन्होंने दूसरी चाबी मंगवाकर तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी प्राप्त कर विकास अधिकारी रामचंद्र की मौजूदगी में तिजोरी को खोला तो उसमें 89731 रुपये नकदी पाई।

अब शराब ठेकों में इलेक्ट्रोनिक तरीके से मिलेगी रसीद, हरियाणा में बंद होगा फर्जीवाड़ा

चंडीगढ़। हरियाणा में शराब की दुकानों में टैक्स चोरी रोकने के लिए इलेक्ट्रानिक तरीके से बिक्री रसीद देना अनिवार्य कर दिया गया है। 15 जनवरी तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं को सेल केंद्रों पर इलेक्ट्रानिक तरीके से बिक्री रसीद की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इससे न केवल गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोका जा सकेगा, बल्कि निगरानी भी सही ढंग से की जा सकेगी। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के आबकारी एवं कराधान उपायुक्तों के साथ बैठक में कहा कि अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए नियमित रूप से छापामारी की जाए। इस दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी एवं आबकारी एवं कराधान आयुक्त शेखर विद्यार्थी ने लाइसेंस शुल्क पर रिपोर्ट रखी। रिकवरी में देरी के मामलों में पेनाल्टी लगाने का निर्देश देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अटैच की गई प्रापर्टी से रिकवरी की जाए। होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हाल में बिना लाइसेंस फीस जमा कराए शराब न परोसा जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश को राजस्व का नुकसान न हो। एक दिन के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस की भी जांच करें और लाइसेंस लिए बिना शराब परोसने वालों पर एक्शन लें। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में अवैध तरीके से शराब की बिक्री रोकने से राजस्व में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। कोविड-19 महामारी के बावजूद पहली छमाही में आबकारी विभाग ने बीते वर्ष के मुकाबले लगभग 660 करोड़ रुपये अधिक राजस्व जुटाया है। उन्होंने कहा कि इस साल 7500 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य तो पूरा करेंगे ही, 20 फीसद अधिक राजस्व भी जुटाया जा सकता है। पहले छह महीने में करीब 4165 करोड़ रुपये का राजस्व आ चुका है।

ये है हरियाणा का बनवाला गांव, महिला सरपंच सुमन ने कर दिखाया कमाल, किसान की जमीन उगल रही सोना

डबवाली। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार पार्ट-1 में तय हुआ था कि गांव की सरकार का मुखिया यानी सरपंच पढ़ा-लिखा होना चाहिए। साथ ही सरपंच प्रतिनिधि जैसे शब्द को समाप्त करते हुए महिला जनप्रतिनिधि को मूल अधिकार नवाजे गए। पांच साल पहले हुए ऐसे निर्णय आज धरातल पर विकास के रुप में नजर आ रहे हैं। आइए... रुख करते हैं डबवाली खंड के गांव बनवाला की ओर। बीए पास सरपंच सुमन देवी कासनियां ने जहां पंचायत को आत्मनिर्भर बना दिया तो वहीं गांव की सालों पुरानी समस्या को चुटकी में हल कर दिखाया। सीधे तौर पर प्रत्येक ग्रामीणों को फायदा पहुंचा तो वहीं ऐसे 40 परिवार लाभान्वित हुए, जिनके पास पंचायत की 108 एकड़ जमीन को जोतने के अलावा आमदनी का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वर्ष 2016 में पंचायत की कमान सुमन के हाथों में आई थी। अगले वर्ष 2017 में पंचायती भूमि का ठेका लेने वाले 40 परिवार आकर रो पड़े कि सालों से वे बीरान भूमि में ग्वार-बाजरी बिजांत करते आ रहे हैं। इतना पानी भी नहीं है कि इन फसलों को बचा सकें। सरपंच ने इस मुद्दे पर अपने पति प्रहलाद कासनियां समेत गांव के बुद्धिजीवियों से चर्चा की। चर्चा के बाद आइडिया मिला कि गांव का भूमिगत जल मीठा है। इस पानी को खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही बोरवैल कर दिए जाएं तो बारिश के दिनों में ओवरफ्लो की समस्या से निजात पाई जा सकती है। फिर क्या था सुमन ने जोहड़ किनारे दो सबमर्सिबल लगाए। करीब 4000 फीट लंबी 14 इंच आरसीसी पाइप लाइन बिछाकर पंचायती जमीन तक पानी पहुंचा दिया। किसानों की किस्मत खुल गई। पिछले तीन सालों से किसान गेहूं और कपास की खेती कर रहे हैं। 9 लाख रुपये ठेके पर छूटने वाली जमीन के बदले पंचायत के खाते में 30 लाख रुपये सालाना आने लगे। आत्मनिर्भर हुई पंचायत ने गांव के विकास के द्वार खोल दिए।

आत्मनिर्भरता ने खोला तरक्की का रास्ता

आत्मनिर्भरता की कसौटी पर पंचायत खरी उतरती प्रतीत हो रही है। खेत-पगडंडियां पक्की होती जा रही हैं। गांव बनवाला के तहत करीब 240 ढाणियां आती हैं। घुकांवाली, नुहियांवाली रोड पर 50-50 ढाणियां हैं, जबकि खारियां रोड पर सर्वाधिक करीब 120 ढाणियां स्थित हैं।

इसके अलावा रत्ताखेड़ा, चक्कां, सादेवाला रोड पर 20 ढाणियां हैं। ढाणियों को जाने वाला रास्ता इंटरलॉक टाइल या फिर ईंटों से पक्का होने लगा है। अब ग्रामीणों को किसी कार्य के लिए कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं बुलाता। न ही फसल की भरी ट्रॉली गड्ढे में फंसती है। बनवाला की सरपंच सुमन देवी कासनियां का कहना है कि गांव के बीचोंबीच बने जोहड़ पर दो सबमर्सिबल लगाने से पंचायत की आमदनी करीब साढ़े तीन गुणा बढ़ गई। वहीं, छह रिचार्ज बोरवैल लगने से जोहड़ ओवरफ्लो की समस्या का समाधान हो गया। साथ ही बरसात के दिनों में गांव में पानी निकासी की समस्या समाप्त हो गई। वहीं भूमिगत जल स्तर स्थाई बना रहने में सहयोग मिला। जो आमदनी हुई, उससे पंचायत ने ढाणियों या खेतों के रास्ते पक्के करवाकर विकास में मील का पत्थर स्थापित किया।

सार-समाचार

अवैध खनन रुकवाने पहुंचे SDM को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, हिरासत में आरोपी

बरेली. उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बेधड़क खनन चल रहा है, जिस वजह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं. बीते मंगलवार शहर के इज्जतनगर के रजपुरा माफी में खनन पर रोक लगाने पहुंचे एसडीएम और उनके स्टाफ को एक माफिया ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलने की कोशिश की. पुलिस की मदद से ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया गया. साथ ही, एसडीएम की ओर से इज्जतनगर थाने में जानलेवा हमला, अवैध खनन समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया गया है.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थे SDM

बीते मंगलवार इज्जतनगर इलाके का दौरा करते हुए एसडीएम को सूचना मिली थी कि रजपुरा माफी इलाके में अवैध खनन चल रहा है. सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे. इस दौरान एसडीएम सदर ने अपने अर्दली मनोज कुमार को ट्रैक्टर-ट्रॉली रुकवाने को कहा, जिसके बाद अर्दली ने चालक से रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने खनन रोकने के बजाय ट्रैक्टर को एसडीएम और अर्दली के ही ऊपर चढ़ाने की कोशिश की.

►**सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे. इस दौरान एसडीएम सदर ने अपने अर्दली मनोज कुमार को ट्रैक्टर-ट्रॉली रुकवाने को कहा, जिसके बाद अर्दली ने चालक से रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने खनन रोकने के बजाय ट्रैक्टर को एसडीएम और अर्दली के ही ऊपर चढ़ाने की कोशिश की.**

जान बचाने के बाद पीछा कर आरोपी को पकड़ा

ट्रॉली को आता देख पहले एसडीएम ने अपने अर्दली के साथ भागकर जान बचाई. उसके बाद ट्रैक्टर के पीछे दौड़कर उसे पकड़ लिया. चालक रामऔतार ने एसडीएम और उनके स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद ड्राइवर को थाने ले जाया गया और ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया. अर्दली मनोज कुमार की ओर से चालक राम अवतार के खिलाफ गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

वाराणसी: 2 और जगहों पर ठहरेगी रेल, रेलवे स्टेशन दिखाएंगे बनारसी संस्कृति की झलक

वाराणसी. राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल मंगलवार को वाराणसी पहुंचे. उन्होंने उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक करके कैंट स्टेशन और शहर में होने वाले ट्रैफिक और भीड़भाड़ को काबू करने का बेहतरीन सुझाव दिया. इससे न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी बल्कि शहर में भारतीय रेलवे के दो और स्टॉप भी बढ़ेंगे. मंत्री रवींद्र जायसवाल ने वाराणसी कैंट स्टेशन के दोनों तरफ से संबद्ध शिवपुर और लोहता स्टेशनों पर ट्रेन को ठहराने की बात कही. कुछ दिन पहले ही मंत्री रवीन्द्र जायसवल ने डीआरएम लखनऊ के साथ वाराणसी के रेलवे स्टेशनों के विकास व उच्चीकरण को लेकर बैठक की थी. उसी वक्त उन्होंने शिवपुर, लोहता और जंसा जैसे स्टेशनों के विकास पर चर्चा की थी. फिलहाल उनके प्रयास के बाद वाराणसी कैंट से आने वाली गाड़ियां अब शहर के आउटर स्टेशन शिवपुर और लोहता पर भी रुकेंगी.

►**मंत्री रवींद्र जायसवाल ने रेलवे के जीएम को बनारस की संस्कृति के अनुरूप कैंट रेलवे स्टेशन का विकास करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कैंट, शिवपुर और लोहता स्टेशनों पर बनारसी घराने का संगीत बजते रहने का सुझाव दिया.**

स्टेशन पर बजेगा बनारसी घराने का संगीत मंत्री रवींद्र जायसवाल ने रेलवे के जीएम को बनारस की संस्कृति के अनुरूप कैंट रेलवे स्टेशन का विकास करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कैंट, शिवपुर और लोहता स्टेशनों पर बनारसी घराने का संगीत बजते रहने का सुझाव दिया. उन्होंने कैंट स्टेशन की दीवारों पर काशी के साहित्यकारों का दोहा और खानपान की जानकारी लिखे जाने का भी निर्देश दिया, जिससे रेलयात्री बोर न हो सके और यात्रा का आनंद उठा सकें. अब वाराणसी शिवपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म का विस्तार कार्य, शौचालयों का निर्माण और आधुनिक वेटिंग रूम का निर्माण जल्दी होने जा रहा है.

मुंगेर से मिले AK-47 मामले में NIA ने गया में की छापेमारी, किंगपिन गिरफ्तार

गिरफ्तार किंगपिन हथियार तस्कर मोहड़ा प्रखंड के तेतर पंचायत का मुखिया है. एनआईए ने गया शहर के मगध कॉलोनी से राजीव रंजन सिंह को गिरफ्तार किया है.

पटना. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की टीम ने गया में सोमवार को छापेमारी कर एके-47 की खरीद-बिक्री मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. एनआईए की टीम ने गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गया जिले के अतरी थाने के अतरी के रहनेवाले मिथिलेश प्रसाद सिंह के बेटे राजीव रंजन सिंह उर्फ चुन्नू सिंह के रूप में की है.

राजीव रंजन सिंह को गिरफ्तार कर एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है. जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किंगपिन हथियार तस्कर मोहड़ा प्रखंड के तेतर पंचायत का मुखिया है. एनआईए ने गया शहर के मगध कॉलोनी से राजीव रंजन सिंह को गिरफ्तार किया है.

बताया जा रहा है कि सात सितंबर 2018 को मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने एके-47 (त्र-47) सीरीज के तीन हथियारों को जब्त किया था. इस मामले में मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाने में सात सितंबर 2018 को प्राथमिकी (कांड संख्या-323/18) दर्ज की गई थी. इसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने एनआइए को सौंपने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी.

वहीं, केंद्र सरकार के निर्देश पर गृह मंत्रालय के अधीन एनआइए ने उक्त मामले को अपने हाथों में ले लिया था. इस मामले में एनआइए की कोर्ट में केस (एनआइए केस आरसी-31/2018) दर्ज किया. मुंगेर पुलिस के द्वारा बरामद की गई एके- 47 व इससे जुड़ी सीरीज की अत्याधुनिक राइफलों की जांच की, तो पता चला कि यह राइफल जबलपुर स्थित राष्ट्रीय आयुध फैक्टरी से जुड़ा है.

ये अत्याधुनिक राइफल प्रतिबंधित हैं. इसका प्रयोग सिर्फ आर्मी, पारा मिलिटरी फोर्स व पुलिस करती हैं. लेकिन इस अत्याधुनिक हथियार की अवैध बिक्री नक्सली संगठन व कुख्यात अपराधियों को भी की जाती रही है.

इसी मसले को जोड़ते हुए एनआईए की टीम ने उक्त मामले की छानबीन की. एनआइए की टीम अब तक इस मामले में 13 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

यूपी में बिजली मीटर की रीडिंग लेने से रोका तो लगेगा जुर्माना, कटेगा कनेक्शन

लखनऊ. घर में आए बिजली कर्मचारी को मीटर रीडिंग से रोकना अब राजधानी वासियों को काफी महंगा पड़ सकता है. लखनऊ में नई व्यवस्था के मुताबिक बिजली कर्मचारी को मीटर रीडिंग लेने से रोकने पर न सिर्फ उपभोक्ता पर जुर्माना लगेगा बल्कि सजा के तौर पर बिजली कनेक्शन भी कट जाएगा. बुधवार से ये व्यवस्था राजधानी लखनऊ में लागू हो चुकी है.

विद्युत कोड में मिला है ये अधिकार

मध्यांचल निगम की ओर से लागू की गई इस व्यवस्था का अधिकार उन्हें विद्युत कोड के अंतर्गत मिला हुआ है. राजधानी में ऐसे उपभोक्ताओं की पहचना का सिलसिला पहले ही शुरू कर दिया गया है, जो कर्मचारियों को मीटर रीडिंग लेने से रोकते हैं. अगर अब उपभोक्ता मीटर की रीडिंग नहीं करने देगा तो उस पर 50 रुपये प्रति किलोवाट/दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा.

पहले नोटिस, फिर कटेगा कनेक्शन

उपभोक्ताओं को पहले इस बात को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा. इस नोटिस का हफ्तेभर तक जवाब न मिलने के बाद बिजली का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के दौरान बिजली विभाग के अफसर के साथ पुलिस भी मौजूद रहेगी. सरकारी काम में बाधा डालने पर उपभोक्ता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है. फिलहाल अधिशासी अभियंताओं से ऐसे उपभोक्ता का ब्यौरा इकट्ठा किया गया है, जो बिलिंग एजेंसी को मीटर रीडिंग करने नहीं देते. उन्हें जल्द ही नोटिस भेज दिया जाएगा.

रीडिंग स्टोर मिली, तो देना होगा दोगुना बिल

खुद ही मीटर की रीडिंग लेकर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के मीटर का सत्यापन किया जाएगा. लेकिन अगर रीडिंग स्टोर मिलेगी तो दोगुने रेट का बिल बनाकर वसूली की कार्रवाई की जाएगी.

बेरहम पति; पत्नी को पीटा, गला दबाया विरोध किया तो दांतों से काट अलग कर दी उसकी जुबान

पत्नी सुमन जब जोर से चिल्लाई तो पड़ोसियों ने आवाज सुन घर में दस्तक दी. आरोपी की पत्नी लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी थी. पास में आरोपी भी बैठा था. इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर आई है. यहां शराब के नशे में पति ने पत्नी से जमकर विवाद किया. पत्नी ने जब इस मारपीट का विरोध किया तो उसकी गर्दन दबाई गई. निर्दयी पति जब ऐसा नहीं कर पाया तो उसने पत्नी की जुबान काट दी. पत्नी की चीख-पुकार सुन परिजनों ने पुलिस की सूचना दी. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पूरा मामला लखनऊ के भट्टा गांव का है. यहां रचित रावत नामक व्यक्ति नशे की हालत में घर पहुंचा. किसी बात पर पत्नी से बहस करने लगा. जब उसने विरोध किया तो पत्नी की जमकर पिटाई करने लगा. पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने पति ने उसकी जुबान अपने दांतों से काट दी. पत्नी की जुबान अलग हो गई थी लेकिन निर्दयी पति उसे पीटता रहा.

पत्नी सुमन जब जोर से चिल्लाई तो पड़ोसियों ने आवाज सुन घर में दस्तक दी. आरोपी की पत्नी लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी थी. पास में आरोपी भी बैठा था. इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल सुमन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने रचित रावत को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया.

Panchayat Election Result को लेकर BJP ने किया तंज, कहा- खुली राज्य सरकार-मंत्रियों की पोल

वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर (Om Prakash Mathur) ने पंचायत चुनाव परिणामों (Panchayati Raj Election 2020) को लेकर राज्य सरकार और प्रदेश कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है.

जयपुर. वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर (Om Prakash Mathur) ने पंचायत चुनाव परिणामों (Panchayati Raj Election 2020) को लेकर राज्य सरकार और प्रदेश कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. माथुर ने कहा कि प्रदेश में सरकार और मंत्रियों की पोल खुल गई और उनका जनाधार समाप्त हो चुका है.

भाजपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर विभिन्न पदों पर काम कर चुके वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर राज्य में पंचायत चुनावों के परिणामों को लेकर उत्साहित हैं. माथुर ने सोशल मीडिया (Social Media) पर इन परिणामों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. माथुर ने लिखा है कि राजस्थान में सम्पन्न पंचायत राज चुनावों के परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की ग्रामीण भारतीयों के प्रति सोच और उनके विकास संकल्प तथा किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उनके हर निर्णय का राज्य का ग्रामण किसान स्वीकार्यता की मोहर लगा रहा है.

राज्य सरकार कांग्रेस पर कसा तंज

चुनाव परिणाम को लेकर ओम प्रकाश माथुर ने राज्य सरकार और प्रदेश कांग्रेस (Rajasthan Congress) पर तंज कसा है. माथुर ने लिखा है कि प्रदेश कांग्रेस ने जिस प्रकार केंद्र सरकार के हर निर्णय का विरोध करती है और जनता को भ्रमित करने का कार्य लगातार कर रही है. इस परिणाम से सरकार और उसके मंत्रियों की पोल खुल गई है. पूरे प्रदेश में उनका जनाधार समाप्त हो चुका है.

कार्यकर्ताओं को दी बधाई

माथुर ने चुनावों में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी. माथुर ने लिखा कि विपरीत परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार सरकारी तंत्र का सामना करते हुए मेहनत को परिणामों में बदला उन्हें बहुत बहुत बधाई.

बिहार में Bharat Band से आम जनजीवन प्रभावित, कृषि कानून वापस लेने की उठी मांग

भारत बंद (Bharat Band) के दौरान बस संचालन में भी देरी हुई. अधिकांश बस ऑपरेटरों ने सुबह के संचालन को रद्द कर दिया. उन्होंने शाम को परिचालन शुरू करने का फैसला किया है.

पटना. राष्ट्रीय जनता दल (RJD), जन अधिकार पार्टी (JAP) और वाम दलों के समर्थकों ने किसानों की ओर से बुलाए गए 'भारत बंद' के समर्थन में मंगलवार को पटना में व्यापक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. इसके अलावा बिहार के कई हिस्सों में कुछ गड़बड़ी और व्यवधान की भी खबरें सामने आईं. पटना में विपक्षी दलों के समर्थकों ने डाक बंगला चौक चौराहे को ब्लॉक कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया.

पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी (जाप) समर्थक विशेष रूप से आक्रामक दिख रहे थे. पार्टी समर्थक अपने सिर पर धान की फसल रखकर संसद की ओर से पारित तीन कृषि विधेयकों का विरोध करते नजर आए. इसके साथ ही वह अपने साथ पारंपरिक कृषि उपकरण भी लिए हुए थे. यादव ने कहा कि राजग सरकार को तीन 'काले कानून' वापस लेने चाहिए और कृषि क्षेत्र पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए.

जाप प्रमुख ने कहा, 'पहले दिन से ही हम तीन काले कानूनों को वापस लेने के अलावा एमएसपी (MSP) पर गारंटी की मांग कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार केवल कॉर्पोरेट घरानों और बड़े कारोबारियों के हितों की बात करती है. वह किसानों के हित की परवाह नहीं करती है. इसके अलावा राजग के नेता उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और राष्ट्रविरोधी कह रहे हैं. यह अस्वीकार्य है. सरकार को हमारे अन्नदाताओं को अपमानित नहीं करना चाहिए.'

पप्पू यादव ने कहा, "हमारी पार्टी ने सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए 16 दिसंबर तक इंतजार करने का फैसला किया है. 23 दिसंबर से हम ऐतिहासिक पश्चिम चंपारण जिले से एक किसान रैली शुरू करेंगे, जो बाद में पूरे राज्य में चलेगी.' विरोध के दौरान, राजद और जेएपी के समर्थकों ने दो दर्जन से अधिक कारों के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वाहन चालकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के विधायक सुदामा प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा, %एनडीए सरकार ने आम लोगों के कल्याण के लिए एक भी निर्णय नहीं लिया है. प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया, रोड टैक्स में वृद्धि की, कॉर्पोरेट्स को लाभ देने के लिए रेलवे और अन्य चीजों का निजीकरण किया. अब वह कृषि क्षेत्र में निजीकरण के लिए तीन कृषि कानून लेकर आए हैं.'

वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा, 'भारत की जीडीपी दर माइनस 23 प्रतिशत है. केवल कृषि क्षेत्र में जीडीपी विकास दर 3.5 प्रतिशत है. मोदी सरकार इस क्षेत्र को कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में लाना चाहती है और किसानों को बंदी बनाना चाहती है.'पटना के डाक बंगला चौक में राजग नेताओं के पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए गए.बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के पोस्टर फाड़ने से बचने की पुलिस की अपील के बाद उनकी पुलिस कर्मियों के साथ मामूली झड़प भी हुई.

भारत बंद (Bharat Band) के दौरान बस संचालन में भी देरी हुई. अधिकांश बस ऑपरेटरों ने सुबह के संचालन को रद्द कर दिया. उन्होंने शाम को परिचालन शुरू करने का फैसला किया है. पड़ोसी जहानाबाद जिले में राजद समर्थकों ने स्थानीय व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किया. उन्होंने ट्रकों और बसों के टायरों की हवा निकाल दी और टायर पंचर कर दिए, जिसके बाद पटना-गया एनएच 83 पर बड़ा ट्रैफिक जाम देखने को मिला. उनकी ड्राइवरों के साथ भी झड़प देखी गई और उन्होंने ड्राइवरों को आगे गाड़ी लेकर जाने से रोक दिया.

गया में जाप समर्थकों ने फ्लाईओवर पर रास्ता अवरुद्ध करने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया. आरा में राजद के समर्थकों ने रेलवे स्टेशन के पास एक कार के विंड शील्ड (आगे का शीशा) को तोड़ दिया. सीपीआई (माले) समर्थकों ने आरा-मोहनिया राज्य राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया. सुपौल में, बंद समर्थकों ने ट्रेनों की आवाजाही बाधित कर दी, जिससे सुपौल-सहरसा मार्ग पर आवागमन में दो घंटे की देरी हो गई. मुजफ्फरपुर में महागठबंधन के समर्थकों ने मुजफ्फरपुर-दरभंगा राज्य राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे एनएच 57 पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला.

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों के खिलाफ दायर जनहित याचिका की खारिज

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को बुधवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह चर्चा में आने के लिये दायर याचिका है न कि जनहित याचिका। इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। याचिका में निजी स्कूलों पर अधिक फीस वसूलने और कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं नहीं संचालित करने का आरोप लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल तथा न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि बिना किसी तैयारी के याचिका दायर की गई। इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन से स्कूल ज्यादा फीस वसूल रहे हैं या ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं होने दे रहे है। अदालत ने कहा कि याचिका में दावा किया गया है कि सही तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं की जा रहीं। अदालत ने याचिकाकर्ता से सही तरीके से का अर्थ पूछा। पीठ ने कहा, इस शब्द का अर्थ बिल्कुल अस्पष्ट है। किसी भी चीज को कहा जा सकता है कि यह सही तरीके से नहीं हो रही। अदालत ने कहा कि यह फिजूल मामला प्रतीत होता है। पीठ ने कहा, यह याचिका बिना किसी तैयारी के दायर की गई। इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह चर्चा में आने के लिये दायर की गई याचिका प्रतीत होती है। यह कहीं से भी जनहित याचिका नहीं है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए चार महीने में जुर्माने की 20 हजार रुपये की राशि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को अदा करने के निर्देश दिए। यह याचिका एंटी-करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट ने अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह के जरिये दायर की थी।

जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 350 परिवारों को वितरित किया राशन और मेडिकल किट

जम्मू। भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के दूर-दराज के इलाकों तथा बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे 350 परिवारों के बीच बुधवार को राशन तथा चिकित्सा सामग्री वितरित की। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सेना ने सुम्बेर पंचायत में चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा शिविर भी लगाया, जिससे घूमंतू गुज्जर तथा बकरवाल समुदाय के सैंकड़ों लोगों तथा पशुओं को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि रामबन जिले की सैन्य इकाई ने महामारी के बीच अपने कोरोना मुक्त अवाम कार्यक्रम के तहत सुम्बेर, डगनारी, बांज, बजोन और मालपट्टी इलाकों में रह रहे 350 परिवारों को राशन और चिकित्सा सामग्री वितरित की। प्रवक्ता ने कहा, इस राहत सामग्री में दूरस्थ तथा ऊंचाई वाले इलाकों में रह रहे लोगों की रोजमर्रा की जरूरत की बुनियादी चीजें शामिल थीं।

शिवसेना ने सामना के जरिये लगाया आरोप, राज्य समर्थित अराजकता को भारत बंद के रुप में जवाब मिला

मुंबई। शिवसेना ने बुधवार को कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा आयोजित किया गया भारत बंद राज्य समर्थित अराजकता को करारा जवाब था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए देश पर भय और आतंक की तलवार लटकाकर रखना चाहती है। सामना में आरोप लगाया गया है 'देश में अशांति का समाधान ढूंढने के बजाय यह अशांति बनाए रखना चाहते हैं।' विभिन्न किसान यूनियनों ने नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया था। संपादकीय में पूछा गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा भारत बंद को समर्थन दिए जाने में क्या गलत था। इसमें किसानों के आंदोलन को देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश बताए जाने और विरोध कर रहे किसानों को खालिस्तानी करार देने के लिए भाजपा की आलोचना की गई। संपादकीय के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा जाति और धर्म के आधार परध्रुवीकरण कर रही है वह राजनीतिक अराजकता है। खून-खराबे और हिंसा की धमकियां दी जा रही हैं, यह अराजकता है। संपादकीय में कहा गया कि अगर किसानों के मुद्दों का तेजी से समाधान हो जाता तो वे घर वापस चले जाते।

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में तीन आतंकियों को किया ढेर

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आंतकवादियों के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ में तीन अज्ञात आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में एक असैन्य नागरिक घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आज तड़के पुलवामा जिले के टिकन इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था।

उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में पहले दो आतंकवादी मारे गए और एक असैन्य नागरिक घायल हो गया था। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर बार मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया। अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों और उनके संगठन की पहचान की जा रही है।

विपक्ष के 5 नेताओं की राष्ट्रपति से मुलाकात, नए कृषि कानूनों को रद्द करने का किया अनुरोध

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच बुधवार को राहुल गांधी, शरद पवार समेत पांच विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। विपक्षी नेताओं ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का अनुरोध किया। विपक्षी दलों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा के महासचिव डी राजा, और डीएमके नेता टीकेएस इलंगोवान शामिल थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें तीन कृषि कानूनों के संबंध में हमारे विचारों से अवगत कराया। हमने इन्हें निरस्त किए जाने का अनुरोध किया। हमने राष्ट्रपति को बताया कि इन कानूनों को वापस लिया जाना बेहद महत्वपूर्ण है।' उन्होंने कहा, 'जिस तरह से ये कानून संसद में पारित किए गए उससे हमें लगता है कि यह किसानों का अपमान है, इसलिए वे ठंड के मौसम में भी प्रदर्शन कर रहे हैं।' कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि नए कानूनों का मकसद कृषि क्षेत्र को 'प्रधानमंत्री के मित्रों' को सौंपना है लेकिन किसान भयभीत नहीं हैं और पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने कहा कि किसान अपना शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि ये कृषि कानून निरस्त किए जाने चाहिए क्योंकि इन पर ना ही संसद की प्रवर समिति में चर्चा की गई और ना ही अन्य पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया। येचुरी ने कहा, 'हमने राष्ट्रपति को बताया कि तीन कृषि कानून अलोकतांत्रिक तरीके से संसद में पारित किए गए और कानूनों को वापस लिए जाने का अनुरोध किया।' कोविड-19 परिस्थितियों के चलते विपक्षी प्रतिनिधिमंडल में केवल पांच सदस्य ही शामिल रहे। सितंबर में बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों को सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश किया है। सरकार का कहना है कि इससे बिचौलिये हट जाएंगे और किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकेंगे। हालांकि, प्रदर्शनकारी किसानों को आशंका है कि नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था और मंडियां खत्म हो जाएंगी, जिससे वे कॉरपोरेट की दया पर निर्भर रह जाएंगे।

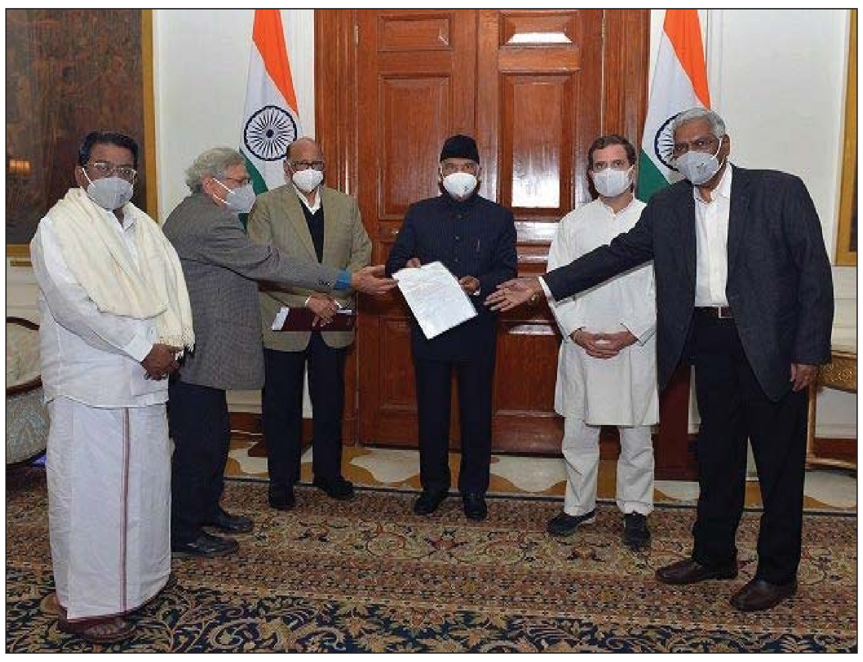

राजस्थान पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले जावड़ेकर, किसान कृषि सुधार पर लगी मुहर

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राजस्थान के पंचायत चुनाव के नतीजों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसानों का फैसलों की मुहर करार दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भाजपा को जीत मिली है। जिला परिषद के इस चुनाव में पूरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के मुख्यतः किसान 2.5 करोड़ वोटर थे, उनका ये फैसला है।

जावड़ेकर ने कहा कि जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें 353 सीटें भाजपा ने जीती हैं। 21 जिला परिषदों में चुनाव हुआ, जिसमे से 14 में भाजपा को बहुमत मिला है और कांग्रेस को केवल 5 में बहुमत मिला है। इन चुनावों में 2.5 करोड़ वोटरों में से अधिकतर किसान हैं, इसका मतलब है कि किसान राजस्थान में कृषि सुधारों के पक्ष में हैं तेलंगाना में अभी हुए हैदराबाद के चुनाव में भाजपा को 49 सीटें मिली जबकि सत्तारूढ़ ञ्क्र को 55 सीटें मिली।

इसके साथ ही जावड़ेकर ने जोर देते हुए कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा को ञ्क्र से अधिक वोट मिले। अरुणाचल में भाजपा को भारी सफलता मिली है। 240 जिला पंचायत के चुनावों में 96 सीटें निर्विरोध आई हैं। ग्राम पंचायत में 8,291 सीटों में से 5,410 सीट निर्विरोध आ गई हैं। राजस्थान के चुनाव में इस बार हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने गृह क्षेत्र के 2 पंचायत समिति पूरी हार गए। पायलट के गृह जिले टोंक में जिला परिषद भाजपा ने जीती है। आने वाले समय के लिए ये शुभ संकेत है कि मतदाता दक्षिण हो या पूर्वोत्तर हो, सभी जगह भाजपा के पक्ष में है। कोरोना महामारी, वैश्विक आर्थिक संकट और विपक्ष का कृषि सुधारों पर दुष्प्रचार के बाद भी मतदाता सभी जगह भाजपा को पसंद कर रहे हैं।

नगर निगम के बकाया राशि को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर गौतम गंभीर, मनोज तिवारी समेत बीजेपी नेताओं ने दिया धरना

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा शासित नगर निगमों के महापौरों और नेताओं द्वारा जारी अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा और इसमें पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और गौतम गंभीर ने भी भाग लिया। दिल्ली के तीन नगर निगमों-उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली, के महापौर जयप्रकाश, अनामिका मिथिलेश और निर्मल जैन कई महिला पार्षदों के साथ सोमवार से केजरीवाल के फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। ये सभी दिल्ली सरकार से 13000 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। धरने में शामिल हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ÷हालांकि केजरीवाल खुद को आम आदमी कहते हैं, लेकिन वह मूल रूप से आम आदमी के खिलाफ हैं।

यही कारण है कि उनकी सरकार ने नगर निगमों को 13000 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान नहीं किया है जबकि इस राशि सेसफाई कर्मियों, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने में मदद मिलती।÷ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष अवधेश गुप्ता ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री संवेदनशील होते तो वह उन निगमों को बकाया भुगतान करते जिनके कर्मचारी कोरोना योद्धाओं के रूप में महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी और प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे नगर निगम के नेताओं से मुलाकात की थी और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। केजरीवाल सहित आप नेताओं ने भाजपा द्वारा शासित तीन नगर निगमों में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाया है और दावा किया है कि समस्त देय धनराशि का निगमों को जारी की जा चुकी है।

कुमारस्वामी बोले, भूमि विधेयक को पारित कराने के लिए जेडीएस ने किया था सरकार का समर्थन

बेंगलुरु। (एजेंसी)।

विवादित कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम 2020 के पारित होने को लेकर भाजपा के साथ गुपचुप सौदेबाजी के आरोपों का सामना कर रही जद (एस) के नेता तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस कानून के कुछ खतरनाक प्रावधानों को वापस लेने पर सहमति बनने के बाद सरकार का समर्थन किया था। कांग्रेस तथा कर्नाटक राज्य रैयत संघ ने कुमारस्वामी पर भाजपा के साथ सौदा करने का आरोप लगाया है। जद(एस) ने कर्नाटक विधान परिषद में मॉनसून सत्र में संशोधन का विरोध किया था जबकि शीतकालीन सत्र में इसका समर्थन किया। इस विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद विधान परिषद में पेश किया गया था। कुमारस्वामी ने कोलार में पत्रकारों से कहा, हमें जिन प्रावधानों पर आपत्ति थी, उनमें से कुछ को वापस लिये जाने के बादजद (एस) ने सरकार का समर्थन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि प्रारंभ में उन्होंने और उनके पिताएच डी देवेगौड़ा ने विधेयक का विरोध किया था, लेकिन कुछ प्रावधानों में बदलाव के बाद पार्टी ने इसका समर्थन किया।

कुमारस्वामी ने कहा, कानून में बदलाव का श्रेय हमें मिलना चाहिये। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने हमारे ध्यान दिलाने पर प्रस्तावित विधेयक के कुछ खतरनाक प्रावधान हटाने का फैसला लिया। जद (एस) नेता ने कहा कि हमारी मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर थी कि पहले सरकार इकाई के तौर पर जमीन की खरीद की सीमा बढ़ाना चाहती थी, जिसके तहत एक परिवार को 248 एकड़ तक जमीन खरीदने की अनुमति थी। कुमारस्वामी ने कहा कि उनके सुझाव पर सरकार ने पिछले सत्र में पुराने प्रावधानों को जारी रखने पर सहमति जताते हुए एक परिवार को 10 इकाई भूमि रखने अनुमति दी। कांग्रेस प्रवक्ता वी एस उगरप्पा ने कहा कि कुमारस्वामी ने दोहरा मापदंड अपनाया है। उन्होंने पीटीआई- से कहा, एक ओर कुमारस्वामी कहते हैं कि उनकी पार्टी किसानों के साथ हैजबकि दूसरी ओर जद (एस) ने कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम पर भाजपा का साथ दिया।

राहुल ने साधा निशाना, कहा- सरकार लोकतंत्र से पाना चाहती है छुटकारा

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह लोकतंत्र से छुटकारा पानी चाहती है। उन्होंने ट्विटर पर दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सुधार, चोरी के जैसा है। गांधी ने ट्वीट किया, ''श्रीमान मोदी के कार्यकाल में सुधार, चोरी के जैसा है। इसलिए वे लोकतंत्र से छुटकारा पाना चाहते हैं।'' नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मंगलवार को एक डिजिटल कार्यक्रम में बयान देने के बाद गांधी ने ट्वीट किया। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा था कि भारत में 'कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है' जिसके कारण यहां कड़े सुधारों को लागू करना कठिन होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि देश को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये और बड़े सुधारों की जरूरत है। स्वराज्य पत्रिका के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये संबोधित करते हुए कांत ने कहा था कि पहली बार केंद्र ने खनन, कोयला, श्रम, कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में कड़े सुधारों को आगे बढ़ाया है। अब राज्यों को सुधारों के अगले चरण को आगे बढ़ाना चाहिए।

कैलाश विजयवर्गीय ने दी दिग्विजय सिंह को नसीहत, अनुभव न हो तो टिप्पणी न करे

इंदौर। (एजेंसी)।

कोरोना वैक्सीन ट्रायल का मामला अब राजनीतिक वाद-विवाद का विषय बनता जा रहा है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच बयान युद्ध शुरू हो गया है। विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को नसीहत दी है कि जिस विषय की जानकारी न हो, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले कारोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर कहा था कि ऐसे समय में जो प्रोटोकाल है, उसके साथ कंप्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो होड़ लग गई है, कौन सी फार्मा कंपनी में कौन से वैक्सीन का यूज किया जाएगा, जिससे हमें बचना चाहिए। देश के लोगों को गिनीपिग नहीं बनाना चाहिए। हरियाणा के मंत्री ने शोहरत पाने के लिए वैक्सीन लिया और उन्हें कोविड हो गया। अब कह रहे हैं कि सेकंड डोज लेना जरूरी है। कोई भी वैक्सीन आता है तो उसका परीक्षण मानव पर करने के पहले एनिमल पर किया जाता है। इस पर बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि भारत किसी वैक्सीन के लिए प्रयोग शाला नहीं हो सकता है।

वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को कहा है कि दिग्विजय सिंह कोई डॉक्टर तो हैं नहीं। जिसमें अपने को नॉलेज नहीं हो, उस बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह एक सीनियर लीडर हैं, इसलिए उन्हें सलाह देता हूं कि आपको यदि इस बारे में अल्पज्ञान है तो टिप्पणी नहीं करें।

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर कहा कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि 90 प्रतिशत किसान उससे दूर हैं। 10 प्रतिशत किसान आंदोलन में शामिल हैं। इस आंदोलन को जो ताकते सपोर्ट कर रही हैं वो इस देश के लिए अलार्मी है। विदेशों में किसान आंदोलन का समर्थन हो रहा है। ये कौन लोग हैं, इसकी गहराई में जाकर सोचना चाहिए कि किसानों के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है।

सऊदी अरब ने किया तुर्की के बहिष्कार का आह्वान, इजरायल की भी सख्त चेतावनी

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

सऊदी अरब ने अपने नागरिकों से तुर्की का बहिष्कार करने के लिए कहा है। मतलब, तुर्की से हर तरह का रिश्ता और वहां की वस्तुओं का इस्तेमाल खत्म करने के लिए कहा गया है। जबकि इजरायल ने नाटो से कहा है कि वह तुर्की की हरकतों पर लगाम लगाए, नहीं तो वह विकल्पों पर विचार करने को बाध्य होगा।

सऊदी अरब के चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजलान अल अजलान ने ट्वीट कर तुर्की की हर चीज का बहिष्कार करने का आह्वान किया। यह बहिष्कार वहां की वस्तुओं के आयात, निवेश और पर्यटन को लेकर होगा। इसमें देश के सभी कारोबारियों और उपभोक्ताओं को भागीदारी निभानी होगी। यह निर्णय तुर्की सरकार द्वारा सऊदी अरब और सऊदी नेतृत्व को नीचा दिखाने वाले बयानों और हरकतों के कारण लिया गया है।

तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने हाल ही में अरब देशों पर क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। एर्दोगन ने यूएई और बहरीन द्वारा इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की निंदा की थी। कहा था कि अरब देश समूचे मध्य-पूर्व क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं। एर्दोगन ने अपने देश की संसद में कहा था कि वह अल्लाह की अनुमति से अपने देश का झंडा पूरे इलाके में फिर से फहराने के लिए प्रयास जारी रखेंगे।

इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्ज ने शांति प्रयासों के खिलाफ तुर्की की हरकतों पर नाराजगी जाहिर की है। गल्फ अरब मीडिया से वार्ता में गेंट्ज ने कहा, तुर्की और ईरान शांति को बढ़ावा देने को तैयार नहीं हैं। वे क्षेत्र में अराजकता की स्थिति बनाना चाहते हैं। गेंट्ज ने कहा, तुर्की का सीरिया, लीबिया और भूमध्य सागर क्षेत्र में हस्तक्षेप शांतिपूर्ण हालात खराब कर रहा है।

तुर्की हमास की भी मदद कर रहा है, जो इजरायल पर आए दिन होने वाले हमलों के लिए जिम्मेदार है। तुर्की की इन हरकतों से क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो रही है। नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के सदस्य के रूप में तुर्की की ये हरकतें बेहद आपत्तिजनक हैं। नाटो तुर्की पर लगाम लगाए, नहीं तो इजरायल विकल्पों पर विचार करेगा।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)